सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

02 मार्च, 2016

टर्न-1/विजय/02.03.16

षोडश विधान सभा बुधवार, तिथि 02 मार्च,2016 ई0

द्वितीय सत्र 12 फाल्गुन, 1937 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

प्रश्नोत्तर काल । तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: महोदय, राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहा है । कल सीवान में 17 लाख रू0 दिन-दहाड़े महोदय गोली चलाकर के लूट लिया । पटना सिटी के खाजेकला के प्लास्टिक व्यवसायी को मारने और हत्या करने का प्रयास किया गया । विधि व्यवस्था की स्थिति ।

श्री श्रवण कुमार: अध्यक्ष महोदय, किस नियम के तहत माननीय विरोधी दल के नेता यह उठा रहे हैं मैं जानना चाहता हूं उनका मकसद क्या है ? कोई भी सवाल उठाना है तो उसके लिये कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है और कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से सरकार जवाब देगी महोदय । ऐसे ही खड़ा होंगे तो उसका जवाब कौन देगा ? महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि नेता, प्रतिपक्ष को गंभीर होना चाहिए और गंभीरता से किसी मामले को उठाना चाहिए । लेकिन गंभीरता से महोदय कहां उठा रहे हैं सवाल ।

तारांकित प्रश्न संख्या-251 (श्रीमती लेशी सिंह)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: कार्यस्थगन महोदय दिया गया है । राज्य में बढ़ते अपराध और राज्य में गिरती विधि व्यवस्था ।

(व्यवधान)

श्री विजय प्रकाश: आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में चरणबद्ध तरीके से भूमि की उपलब्धता के आधार पर 54 अनुमंडलों में नया आई0टी0आई0 संस्थानों के लिए 16.02.16 की मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति दी जा चुकी है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी आपका उत्तर तो परिचारित है अब तो मा0 सदस्या पूरक पूछेंगी ।

श्री विजय प्रकाश: हम बता देते हैं सर डिटेल ।

अध्यक्ष: नहीं डिटेल तो आपका उत्तर आया हुआ है । बल्कि आपको आसन की तरफ से इसके लिए धन्यवाद है कि आपने समय पर उत्तर भेज दिया है । आपके विभाग से जो परिचारित है । जो आज का आर्डर पेपर है उसके साथ यह परिचारित है अब माननीय सदस्या आपसे पूरक पूछेंगी ।

श्रीमती लेशी सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्णिया जिला पदाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर जमीन संबंधी प्रस्ताव चिन्हित करके भिजवा दूंगी तो क्या माननीय मंत्री महोदय वित्तीय वर्ष 2016-17 में धमदाहा अनुमंडल में आई0टी0आई0 खोलने का विचार रखते हैं ?

श्री विजय प्रकाश: महोदय, सुशासन के निश्चय में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो तय किया है कि चरणबद्ध तरीके से 54 अनुमंडलों में हमलोगों को, 16.02.2016 के मंत्रिपरिषद की बैठक में भी तय हो चुका है, इसको चरणबद्ध तरीके से हर अनुमंडल में आई0टी0आई0 स्कूल खोलने का । हमलोग निर्देश भेज चुके हैं सभी जिला पदाधिकारियों को कि जमीन की उपलब्धता करायें और इसको चरणबद्ध तरीके से किया जाय कॉलेज का ।

अध्यक्ष: आपको पूरक पूछना है तो पूछ लीजिये ।

श्रीमती लेशी सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से जमीन चिन्हित हो जाने पर खोला जाएगा सभी अनुमंडल मुख्यालय में । मैं माननीय मंत्री महोदय से जो पूरक प्रश्न पूछी उसमें स्पष्ट मैंने माननीय मंत्री से सरकार से जानना चाहा कि क्या वित्तीय वर्ष 2016-17 में धमदाहा अनुमंडल में आई0टी0आई0 की स्थापना करने का विचार रखते हैं ? हमें मंत्री जी का स्पष्ट जवाब नहीं मिला ।

श्री विजय प्रकाश: हम आपके सुझाव के अनुसार 2016-17 में इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष: मा0 सदस्य, श्री नंद किशोर जी ।

श्री नंद किशोर यादव: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में सुशासन के कार्यक्रम का जिक्र किया है महोदय । मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2010-2015 में जो पुस्तिका छपी थी उसके पृष्ठ 9 पर यह बात अंकित है कि राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में लघु औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थान, सभी अनुमंडलों में एक एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किये जायेंगे । महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब 2010-15 के राज्य के सुशासन के कार्यक्रम में सभी अनुमंडल में एक एक औद्योगिक संस्थान खोलने का

...

निश्चय था तो क्या कारण है कि अब तक इस छठे वर्ष भी पांच वर्ष में जो काम पूरा करना था इस वर्ष भी काम पूरा नहीं हुआ । कारण क्या है ?

श्री विजय प्रकाशः मा0 सदस्य जो बोल रहे हैं पहले से जो किया हुआ है जमीन नहीं मिल पाया था उस समय आपलोग साथ थे जमीन नहीं दे पाये थे और हमलोग उसको प्रयास कर आगे बढ़ा रहे हैं ।

अध्यक्षः मा0 सदस्य, नंद किशोर बाबू माननीय मंत्री का कहना है कि आपने जो सुशासन के कार्यक्रम 2010 से 2015 तक जो जिक्र किया उसी काम को सरकार आगे बढ़ा रही है । जमीन चिन्हित करा रही है और जैसे ही जमीन चिन्हित होगी आई0टी0आई0 खोला जाएगा ।

श्री नंद किशोर यादवः पांच साल में जमीन चिन्हित नहीं हुआ महोदय, बनेगा कब ? महोदय माननीय मंत्री महोदय का जो जवाब है बड़ा हास्यास्पद है । हमें आपका संरक्षण चाहिए महोदय । यह सुशासन का कार्यक्रम महोदय सिर्फ वक्तव्य नहीं है किसी नेता का । यह सुशासन का कार्यक्रम मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत है महोदय । और इसीलिये इस बात का निर्णय लिया गया था कि पांच साल में हर अनुमंडल में पॉलटेकनिक खोला जाएगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। महोदय क्या कारण है कि नहीं खोला गया । जवाब नहीं दे रहे हैं मंत्री महोदय । आखिर पांच साल तक क्यों नहीं खोला गया इसका जवाब चाहिए । क्या सरकार ने पांच साल तक कोई काम नहीं किया इसके लिए,कोई प्रयास नहीं किया । इसका भी जवाब चाहिए महोदय । हम जानना चाहते हैं महोदय ।

श्री विजय प्रकाशः माननीय सदस्य की बातों को हम सुन रहे हैं ।

श्री विजेन्द्र प्र0 यादवः महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं मेरे यहां तय हुआ था इस कार्यक्रम में कि हर अनुमंडल में एक आई0टी0आइ0 खुलेगा महिला आई0टी0आई0।मेरे यहां तो आधे से ज्यादा बिल्डिंग बन गया है । जहां जमीन उपलब्ध हुआ वहां का कार्य प्रगति पर है । जहां जमीन नहीं मिला है बारी-बारी से उसको किया जा रहा है । ऐसा नहीं है कि जीरो पर खड़े हैं । ऐसी बात नहीं है । लेकिन जमीन की कठिनाइयां बिहार में है यह सबको विदित है सबको मालूम है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-252 (श्रीमती भागीरथी देवी)</u>

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास । यह जल संसाधन विभाग से स्थानंतरित हुआ था । अत: स्थगित किया जाता है ।

श्री शैलेश कुमार : समय चाहिए ।

अध्यक्ष: यह स्थगित हुआ ।

श्रीमती भागीरथी देवी: हुजूर क्या हुआ ?

....

अध्यक्ष: स्थगित हुआ है अगले दिन आएगा ।

श्रीमती भागीरथी देवी: का मंत्री जी ना आइल बानी का हुजूर । हर विभाग के मंत्री जी के आवे के चाहीं । कोई ऐने लुक जा तानी, कोई ओने लुका जा तानी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-253 (श्री दिनेश चन्द्र यादव)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री राजीव रंजन सिंह: महोदय खंड-1: आंशिक स्वीकारात्मक है ।

सहरसा जिला अंतर्गत पूर्वी कोशी तटबंध से सटे पूर्वी भाग में महीषी एवं सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड की सितुहा आदि इलाके एवं बैरीया चौराही, करगी, सहारपुर इत्यादि गांव के लगभग दस हजार एकड़ भू-भाग में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है । वर्तमान में 23 उंची भूभाग पर मक्के एवं गेहूं की खेती की गयी है ।

खंड-2: प्रश्नागत क्षेत्र में कहीं कहीं सड़क एवं पुल पुलिया का निर्माण हो जाने एवं सिल्टेशन के कारण जल निकासी समुचित रूप से नहीं हो पाती है ।

खंड-3: मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णिया को विभागीय पत्रांक 236 दिनांक 1 मार्च, 2016 द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे स्वयं स्थल निरीक्षण करके एक माह के अंदर योजना प्रतिवेदन समर्पित करें ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव: अध्यक्ष महोदय, यह उस इलाके के लिए बहुत जटिल समस्या है और माननीय मंत्री जी को जो हम समझते हैं कि विभाग जानकारी उपलब्ध कराये । इसको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है । हम माननीय मंत्री जी को उनके जवाब पर कोई चुनौती नहीं देना चाहते है लेकिन फिर भी कोशी तटबंध के पूर्वी हिस्से में भीमनगर से लेकर कोपड़िया 125 से 123.5 कि0मी0 तक जो उस होकर गुजरे हैं हम समझते हैं प्राय: सभी मंत्री उधर से गुजरे है वहां की पीड़ा को समझे हैं । और उसमें जो स्लुइस गेट से पानी अभी निकल नहीं पा रहा है ।

क्रमशः

टर्न–2/बिपिन/02.03.16

श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्रमशः और उसमें जो ठेंगरा ड्रेनेज, बलुआहा ड्रेनेज है, यह सब नदी, जो भी चौवहरा से सुपौल जिला के तरफ आती है....

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव: हॉ,प्रश्न पूछ रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि जो पानी निकलना चाहिए उस पानी का जो ठेंगरा ड्रेनेज है, 1984 में जब बाढ़, तटबंध टूटा था रहिका के नजदीक, तो वह ड्रेनेज करीब-करीब भर गया । जब ड्रेनेज भर गया तो किसने जवाब बना कर दे दिया कि मक्का की खेती, गेहूँ की खेती होती है । इस तरह का जवाब नहीं आना चाहिए । इसलिए हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि वहां के लोग की पीड़ा को देखते हुए जो वहां छः स्लुइश गेट था पानी निकलने के लिए, चार ध्वस्त हो गया, एक काम नहीं करता, एक स्लुइश गेट जो कोपैया के नजदीक है जो तटबंध का सेवा पथ बन रहा था उसी प्रोजेक्ट में वह इन्क्लुड था उसका भी निर्माण नहीं हुआ और पानी जो ढेंगरा ड्रेनेज का सतह उपर उठ गया है तो क्या माननीय मंत्री जी विशेष टीम गठित कर भेज कर इस समस्या का निदान कराना चाहेंगे क्या?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ने तो बताया कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्थल अध्ययन करके प्रतिवेदन देने के लिए तो उन्होंने तो अपने जवाब में बताया।

श्री दिनेश चन्द्र यादव: अध्यक्ष महोदय, आपने तो कह दिए कि सीधे प्रश्न पूछिए। हम वस्तुस्थिति बताना चाहते हैं कि कोश्चयन मेरा नहीं है, क्वेश्चन सदन का है और इस इलाके के जो पीड़ित लोग हैं उनका यह प्रश्न है।

अध्यक्ष: ठीक है, माननीय मंत्री जी।

श्री राजीव रंजन सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बता रहे हैं कि पीड़ा है, पीड़ित हैं लोग, हमने उत्तर में बताया कि जगह-जगह पुल-पुलिया बन जाने के कारण बांध के अंदर पानी का जमाव हो जाता है । इसको मैंने स्वीकार किया है उत्तर में कि वहां जल जमाव होता है और मैंने यह भी कहा कि एक महीना के अन्दर चीफ इंजीनियर को कहा गया है कि वह स्वयं स्थल निरीक्षण करें और स्वयं स्थल निरीक्षण करके रिपोर्ट दें।

श्री दिनेश चन्द्र यादव: अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो जल निकासी का रास्ता है स्लुइश गेट 123 कि0मी0 पर कोपरिया के नजदीक, जो तटबंध पक्कीकरण के योजना में सम्मिलित है, उसी से होकर सारा पानी निकलता है तो जब उस प्रोजेक्ट में सम्मिलित हैं, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उस काम को भी कब तक शुरू करा देंगे, यह हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह: महोदय, माननीय सदस्य जो स्लुइश गेट की बात बता रहे हैं, हम मुख्य अभियंता को यह भी निर्देश देंगे कि माननीय सदस्य से सम्पर्क कर लें और इनको भी स्थल निरीक्षण के दौरान रख लें । जहां जो असुविधा होगी, वह बतायेंगे, उसको दूर करने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री सदानन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है अपने उत्तर में कि कोशी पूर्वी तटबंध के पूर्वी भाग में जल जमाव है । तो माननीय मंत्रीजी कृपया यह बताएंगे कि पूर्वी कोशी के तटबंध में विभाग में अभी सरकारी आंकड़े के अनुसार जल-जमाव कितने एकड़ में या कितने हेक्टेयर में है ?

श्री राजीव रंजन सिंह: महोदय, यह बहुत बड़ा इलाका है, लगभग एक सौ एकड़ से ज्यादा का इलाका है जहां वह जल-जमाव होता है लेकिन मैंने यह भी बताया कि उसके उपरी भाग में मक्के की खेती होती है ।

श्री नीरज कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, वह 120 किलोमीटर का एरिया है और 120कि0मी0 पर 10हजार एकड़ से ज्यादा जमीन फॅसा हुआ है और पिछले विधान सभा में भी, 15वीं विधान सभा में भी यह मामला हमलोग लाए थे लेकिन अभी तक उस पर जांच ही चल रहा है, उसपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है । यह सरकार की विडम्बना है महोदय कि 10हजार से ज्यादा एकड़ जमीन फॅसा हुआ है । किसान ...

अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री नीरज कुमार सिंह:महोदय, हम चाहते हैं कि अविलम्ब, कब, यह समय सीमा निर्धारित कर दें कि कब से इस पर कार्रवाई होगी और जमीन जो जल-जमाव से डूबा हुआ है उस जमीन पर कब से खेती हमलोग, किसान कर पाएंगे ? हम यह महोदय से जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य माननीय मंत्री ने यह बताया है कि उन्होंने मुख्य अभियंता को स्वयं इसका निरीक्षण करके एक महीना के अंदर निदान बताने को कहा है ।

श्री नीरज कुमार सिंह: महोदय, माननीय मंत्री से हम यह भी जानना चाहते हैं कि यह कोई नया मामला नहीं है । यह वर्षो से, जबसे बांध बना है तबसे, लगभग 20वर्ष पहले का मामला है, वर्षो से यह मामला चलता आ रहा है लेकिन अभी तक उसका निदान नहीं हो पाया । माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में अभी आया है, हम चाहते हैं कि अविलम्ब इस पर कार्रवाई हो ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 254(श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव)</u>

श्री शैलेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि एन.एच.-28पिपरा चौक से भेरखिया पथ तक की कुल लम्बाई 9.5कि.मी. है जो क्षतिग्रस्त है । पिपरा चौक से 05कि0मी0 पर बाही टोला के पास पांच मीटर गुणे तीन मीटर आकार का पुल है जो अभी क्षतिग्रस्त है । पुल का निर्माण नहर विभाग, मोतिहारी द्वारा पूर्व में किया गया था एवं पुल सिंचाई विभाग के अधीन है । इस पथ को अनुरक्षण श्रेणी-वन के प्राथमिकता सूची के क्रमांक-1 में शामिल कर लिया गया है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकतानुसार पथ की मरम्मती का कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, यह जो सड़क है यह इलाका किसान बहुत क्षेत्र है और वहां के किसान के लिए चीनी मिल जो चकिया था वह बंद पड़ी हुई है और वहां से गोपालगंज के तरफ सिधवलिया जाता है और इतनी स्थिति खराब है उस रोड का कि वहां किसान को गन्ना पहुँचाने में दिक्कत हो रही है। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि जितना जल्दी हो वह रोड बनाने और पुल, समय-सीमा निर्धारित करने की कृपा करें कि कितना दिन में पुल बन कर तैयार हो जाएगा और सड़क का काम पूरा हो जाएगा ?

श्री शैलेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, हमने बताया है कि पुल सिंचाई विभाग के अधीन है । दूसरी बात है, जहां तक माननीय सदस्य का कहना है सड़क संबंधी तो वह श्रेणी वन में है तो उसको तो हम बना ही डालेंगे, निधि की उपलब्धता जब हो जाएगी तो प्राथमिकता सूची में उसको हम बना डालेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार: अध्यक्ष महोदय, यह सड़क मेरे क्षेत्र होकर गुजरती है जो मोतिहारी के मधुबनी घाट बथनाहा होकर आती है और पुल के उस पार मेरा, जहां पुल बनने की बात हो रही है, पुल के उस पार मोतिहारी कंस्टिचुएन्सी है, इस पार पिपरा कंस्टिचुएन्सी है । उसके बाद पकड़ीदयाल अनुमंडल है और पकड़ीदयाल अनुमंडल से सीधा रेलवे स्टेशन जोड़ने वाला यह पथ है । तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो पकड़ीदयाल अनुमंडल से यह पथ जा रही है, मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि पकड़ीदयाल अनुमंडल से चकिया भाया मोतिहारी वथनाहा मधुबनी होकर, इस पथ को उस अनुमंडल से जोड़ते हुए पूरा जो जर्जर है सबको निर्माण कराने का विचार रखते हैं ? हॉं तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-255 श्री संजय सरावगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वह दूसरे सड़क का भी इसमें शामिल करा दिए न !

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप आसन की तरफ मुखातिब न होकर सीधे क्यों हो जाते हैं ? आप जो भी पूछते हैं आप सदन के माध्यम से न पूछते हैं !

हम यह कह रहे थे कि वह तो माननीय सदस्य श्यामबाबू यादव जी का प्रश्न था, आप उसके साथ, आपने श्याम बाबू यादव जी के सड़क के साथ अपनी एक सड़क जोड़ डाली । वह मैं सुन रहा था । इसलिए हमने कहा कि मंत्री जी ने सूचना ग्रहण कर ली है । आप वाला भी देखेंगे । इसलिए हम आगे बढ़ गए।

<u>प्रश्न संख्या-255 (श्री संजय सरावगी)</u>

श्री कपिलदेव कामतः अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । गृह आरक्षी विभाग के पत्रांक 439 दिनांक 20.1.2015 द्वारा पंचायती राज विभाग को सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 27.11.2013 को माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन द्वारा पंचायती राज विभाग के समीक्षा के क्रम में यह निर्देश देने की कृपा की गई थी कि ग्राम कचहरियों को नोटिस तामिला कराने हेतु चौकीदारों की सेवा दी जाए ।

2. उत्तर अस्वीकारामक है । वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम कचहरी के वादों के नोटिस तामिला कराने हेतु चौकीदारों की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में विभागीय पत्रांक 8प वि5-123-2013/1616 दिनांक 252.14 द्वारा गृह विभाग से अनुरोध किया गया था । पुनः विभागीय पत्रांक 8प वि प 123- 2013/694 दिनांक 4.2.15 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी पुलिस अधीक्षक बिहार को गृह आरक्षी विभाग के पत्रांक 439 दिनांक 20.1.15 के आलोक में ग्राम कचहरी के वादों को नोटिस तामिला कराने के लिए चौकीदार का सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश अपने स्तर से सभी थाना प्रभारियों को भी देने के लिए अनुरोध किया गया है ।

श्री संजय सरावगी:- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 दिसम्बर, 2013 को इसी सदन में, सरकार ने, पंचायत में सरपंच को सरकारी कर्मचारी के रुप मे चौकीदार को सम्बद्ध करने की घोषणा की थी लेकिन पूरे बिहार में अध्यक्ष महोदय कहीं भी चौकीदार की सेवा सरपंच को नहीं मिला है, खुद नोटिस पर हस्ताक्षर करते हैं, वही जाकर तामिला कराते हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी भी कह रहे हैं कि चिट्ठी चली गयी है, तो पत्र का आदान-प्रदान हो गया लेकिन व्यवहारिक रुप से मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, यह कहीं भी तामिला नहीं हो रहा है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी पूरी समीक्षा करके और धरातल पर कब तक इसको करेंगे, जरा बतावें कि कब तक यह तामिला होगा, जिससे चौकीदारों की सेवा सरपंच को मिल जायेगा ?

अध्यक्ष:- आप भी नंद किशोर जी पूछ ही लीजिये। नहीं इनका तो सुझाव है ।

श्री संजय सरावगी:- महोदय, मेरा सुझाव नहीं बल्कि प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पत्र चला गया है, पत्र का आदान प्रदान हो गया लेकिन अभी तक सेवा मिली नहीं है तो कब तक इसकी समीक्षा कराकर इसको लागू करायेंगे।

अध्यक्ष:- माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आपने जो घोषणा के हिसाब से सरकार की अधिसूचना जारी की है, वह धरातल पर लागू नहीं हो पा रहा है, तो वे कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा करके इसको लागू करवाइये ।

श्री कपिलदेव कामत:- महोदय, इसकी समीक्षा कर लागू कराने की दिशा में पहल किया जायेगा।

श्री संजय सरावगी:- महोदय, कब तक, एक समय सीमा तो बता दें ।

श्री कपिलेव कामत:- महोदय, पंचायत चुनाव के बाद इसे पूरा कर लिया जायेगा।

श्री नंदकिशोर यादव:- महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री ने 2013 में इस बात का निदेश दिया था कि सभी ग्राम कचहरी को चौकीदार मिले और माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को भी स्वीकार किया है कि जनवरी, 2015 में गृह विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया है कि ग्राम कचहरी को चौकीदार उपलब्ध कराया जाय, खुद आपने भी पढ़ा है पत्रांक-दिनांक सब, तो महोदय हम जानना चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्री के निदेश के बाद, 2013 में निदेश देते है मुख्यमंत्री,

2015 में गृह सचिव चिट्ठी भेजते है और एक साल पूरा हो जाने के बाद भी अगर किसी कर्मचारी ने, अधिकारी ने, मुख्यमंत्री के निदेश के बावजूद, गृह

..

सचिव के निदेश के बावजूद भी, इसका क्रियान्वयन नहीं किया है, तो सरकार ने किन-किन लोगों पर कार्रवाई की है मुख्यमंत्री के निदेश के अवहेलना पर, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः- महोदय, अगर स्पेसिफिक माननीय सदस्य बतावें कि अमुक-अमुक सरपंच ने सूचना भेजी और थाना प्रभारी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो निश्चित रुप से सख्त कार्रवाई की जायगी .... (व्यवधान)

अध्यक्षः- अब आपका फॉरफिट हो गया ।

श्री नंदकिशोर यादवः- महोदय, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, यह तो माननीय मंत्री ने कहा है कि यह निदेश दिया गया और निदेश का पालन नहीं हुआ, समीक्षा की बात की जा रही है .... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः- अध्यक्ष महोदय, जब सरकार का निदेश अनुपालन नहीं हुआ, तो ये स्पेसिफिक बतावें कि किस-किस पंचायत के सरपंच ने कार्रवाई के लिए रिक्यूजिशन दिया और थाना ने इम्प्लीमेंट नहीं किया।

श्री नंदकिशोर यादवः- महोदय, पटना जिला के पटना सदर प्रखंड के महौली पंचायत में नहीं मिला। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री ने निदेश दिया, गृह सचिव ने चिट्ठी इशू किया, तो जो पालन नहीं किया गया मुख्यमंत्री जी के निदेश का, तो ये किन लोगों पर कार्रवाई की, ये जवाब दें, अनेकों उदाहरण है और मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि नहीं जवाब दिया गया है, यह कैसा शासन है महोदय कि मुख्यमंत्री के निदेश का भी पालन नहीं हो रहा हो, इससे भयंकर बात और क्या हो सकती है महोदय।

अध्यक्षः- माननीय मंत्री जी, माननीय नंदकिशोर जी का कहना है कि पटना जिला के पटना सदर प्रखंड के महौली पंचायत में आपका जो यह दिशा-निदेश है, यह लागू नहीं हुआ है, आप इसकी जांच करा लीजिये .... (व्यवधान)

श्री संजय सरावगीः- महोदय, मेरे पास भी नाम है। ा

अध्यक्षः- अब आपका नहीं होगा ा

श्री नंदकिशोर यादवः- महोदय मैंने एक उदाहरण दिया लेकिन यह मामला पूरे बिहार के ग्राम पंचायतों के ग्राम कचहरी में लोग बहाल नहीं किये जाय, सरकार के आदेश के बावजूद .... (व्यवधान)

अध्यक्ष:- अब हो गया।

श्री सदानंद सिंह:- अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय .... (व्यवधान)

श्री नंदकिशोर यादव:- महोदय, मेरा आग्रह होगा यह जो दिखाई पड़ रहा है सदन का रुप, मेरा आग्रह होगा कि मंत्री जी पुनः इसकी समीक्षा कर लें, अभी इसको स्थगित ...

कर दीजिये और अगले सप्ताह में बतायें कि कहाँ-कहाँ ये दे पाये हैं सरकार बताये, हम तो कह रहे हैं कि कहीं नहीं मिला है महोदय।

श्री सदानंद सिंह:- अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर कहीं किसी भी पंचायत में इसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश जरुर है, सरकार को आपकी ओर से यह निदेश जाना चाहिए कि इसका कार्यान्वयन सख्ती से कराये, इससे काम चल जायेगा।

अध्यक्ष:- सरकार इसको दिखवायेगी। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, चूंकि अब पंचायत से संबंधित निर्वाचन की प्रक्रिया शुरु हो रही है, इन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद इसको सख्ती से लागू कराया जायेगा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव:- माननीय सदस्य सदानंद बाबू जो कह रहे हैं, इस बात को स्वीकारना होगा .... (व्यवधान)

श्री सदानंद सिंह:- हम स्वीकार करते हैं, हम तो जानते है, रोज दिन गाँव को देखते हैं, कहीं नहीं हो रहा है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव:- आप पहले मेरी बात को सुन तो लीजिये। महोदय, यह सच है कि पंचायती राज व्यवस्था में सरपंचों की जो भूमिका है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा ठीक-ठाक करने में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा हैं, जहाँ के सरपंच एक्टिव होते हैं, वहाँ निश्चित रुप से कार्रवाई होती है लेकिन यह सच है कि जेनरल नहीं हो पा रहा है।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 256 (श्री जर्नादन मांझी)</u>

श्री शैलेश कुमार:- अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण मननपुर-अमरपुर पथ से लौसा भाया रघुनाथपुर तरडीह पथ संख्या-बी0आर0/03आर0/44 के नाम से एन0बी0सी0सी0 द्वारा दिनांक 28.2. 2009 को कराया गया है। उक्त पथ में अनुरक्षण की अवधि दिनांक 28.2.2014 को समाप्त हो चुकी है। पथ की लंबाई 5.65 किलोमीटर है। उक्त पथ को श्रेणी-2 में शामिल किया जा रहा है। तत्पश्चात् निधि की उपलब्धता के आधार

पर प्राथमिकता के अनुसार उक्त पथ का मरम्मति कराया जाना संभव हो सकेगा।

श्री जर्नादन मांझी:- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पथ पहले ग्रामीण पथ था लेकिन चानन नदी पर पुल बन जाने से, मुख्यमंत्री सेतु बन जाने से, धोरैया विधान सभा और अमरपुर विधान सभा दोनों को जोड़ने वाली इस पथ का महत्व बढ़ गया है

....

और यह पथ इतना जर्जर है, जो एन0बी0सी0सी0 से काम हुआ है, अगर उसमें नहीं काम किया जायेगा, क्योंकि इसपर ट्रैफिक ज्यादा हो गया है, चूंकि अब दो विधान सभा को जोड़ने वाला मुख्यमंत्री सेतु बन जाने से चानन नदी पर इस पथ का महत्व बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसको इसी वित्तीय वर्ष में मरम्मति करा दिया जाय।

टर्न-04/कृष्ण/02.03.2016

तारांकित प्रश्न संख्या : 256 (श्री जर्नादन मांझी) क्रमशः

श्री शैलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की गंभीरता को समझते हुये इसको श्रेणी-2 में हमने लिया । लेकिन हम इसको दिखवा लेते हैं ।

श्री विजय कमार सिन्हा : महोदय, एन0बी0सी0सी0 द्वारा जो सड़क बनाया गया पूर्वांचल जिलों में और उसे आधा-अधूरा छोड़ दिया गया तो क्या उन पर कारवाई करते हुये उनकी सेक्यूरिटी मनी जप्त किया गया है यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री शैलेश कुमार : महोदय, इस संबंध में हमलोगों ने कई बार केन्द्र को भी कहा कि वह केन्द्र प्रोयाजित था, वे लोग कर रहे थे और वे अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं । उनकी पांच एजेंसी जो बिहार में रोड बनाया है, वे सब जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं । हम इधर भी पत्राचार किये हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 257 (श्री रत्नेश सादा)

श्री शैलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन की पथ 03 से सुरमाहा नाम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक 31 के लिंक संख्या 037 के रूप में अंकित है । उक्त पथ की लंबाई 2 कि0मी0 है तथा वर्तमान में कच्ची है । एन0आर0आर0डी0ए0 भारत सरकार की स्वीकृति के पश्चात् उक्त पथ का निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उक्त पथ से चलने के लिये ग्रामीणों को काफ कठिनाई होती है और पक्की सड़क तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस पर जान-माल भी नहीं चल पाते हैं । मैं आपके माध्यम से जानना माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कबतक इस सड़क का पक्कीकरण करायेंगे ?

श्री शैलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमने अपने जवाब में कहा कि भारत सरकार की स्वीकृति के पश्चात् चूंकि यह पी0एम0जी0एस0वाइ0 के कोर नेटवर्क में है, उसके पश्चात् ही हम कर सकते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 258 (श्री सीताराम यादव)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि निम्न धार में बछराजा नदी पर लघु जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व से ग्राम कटैया एवं दामोदरपुर अहियापुर के निकट दो गेटेड वीयर का निर्माण कराया गया है एवं ग्राम भईयापट्टी के निकट एक गेटेड वीयर का निर्माण कराया जा रहा है । इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग द्वारा बछराजा नदी

पर ही प्रश्नगत स्थल के निम्न धार में ग्राम अकौर के समीप एक गेटेड वीयर का निर्माण कराया गया है, जिससे पटवन हो रहा है । विगत तीन वर्षों में क्रमश 360 हे0, 180हे0 एवं 115 हे0 क्षेत्र में सिचाई उपलब्ध करायी गयी है । विगत कुछ वर्षों से वर्षा की कमी के कारण बछराजा नदी में सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण पूर्व से निर्मित वीयरों से लक्ष्य के अनुरूप सिंचाई नहीं हो पा रही हैं ।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में स्लूईस गेट का निर्माण कराने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री सीताराम यादव : यह बरसाती नदी नही है । सालो भर इसमें पानी रहता है । यह स्थाई नदी है । केन्स नहर का और कमला नहर का मेन कैनाल है, उसका पानी उसमें बराबर गिरता रहता है । पानी का इसमें कोई अभाव नहीं रहेगा । इसके बन जाने से हजारो-हजार एकड़ की सिंचाई होगी । यह बनना निहायत जरूरी है किसान के हित में । उस इलाके का बहुत बड़ा कल्याण होगा । मैं आपके मार्फत मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह बन जाने से सरकार को भी लाभ होगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा । यह बहुत जरूरी है । पानी का कहीं कोई अभाव नहीं है । मंत्री महोदय इसकी जांच करा लें, पदाधिकारी ने गलत सुझाव दिया है । उसके वहां बनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बताया, पिछले तीन वर्षो का आंकड़ा देकर बताया कि पहले साल 360 हे0, उसके बाद 160 हे. और उसके बाद 115 हे0 तीन सालों में वर्षो की कमी के कारण हमारा जो लक्ष्य है, जो क्षमता ऑलरेडी सृजित है, उस क्षमता के अनुरूप भी हम जल व्यवस्था सिंचाई के लिये नहीं करा पाये । अतिरिक्त क्षमता अगर सृजित कर दिया तो जो हमारी वर्तमान की जो क्षमता है, उसमें भी ह्रास होगा । फिर भी माननीय सदस्य अगर यह कह रहे हैं कि वहां पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो हम इसको फिर से जरूर दिखवायेंगे । अगर वहां पानी की प्रचुर मात्रा है तो निश्चित तौर पर जल का उपयोग सिंचाइ के लिए होना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आपके लाईन में ही जवाब दिया ।

श्री सीताराम यादव : अध्यक्ष महोदय,जब पदाधिकारी जांच के लिये वहां जाये तो हमलोगों को बोल देंगे, हमलोग भी वहां साथ में रहेंगे, क्योंकि गलत सूचना है । माननीय मंत्री से इतना आश्वासन मिल जाय कि हमलोगों की उपस्थिति में पदाधिकारी जांच के लिये जाये और वहां जांच हो ।

श्री राजीव रंजन सिंह, उर्फ ललन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या आपत्ति है ? अगर कमी होगी, माननीय सदस्य लोग दिखा देंगे कि कमी है और अगर अतिरिक्त होगा तो माननीय सदस्य के अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार होगा । माननीय सदस्य भी स्थल निरीक्षण में उपस्थित रहें, इसमें क्या आपत्ति हैं ?

तारांकित प्रश्न संख्या : 259 (श्री रामचन्द्र सहनी)

अध्यक्ष : मा0स0श्री रामचन्द्र सहनी जी ने मा0स0 श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह को अधिकृत किया है ।

श्री शैलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 2 किलोमीटर है । यह पथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2012-13 में स्वीकृत है । संवेदक द्वारा 1.5 कि0मी0 मिट्टी कार्य एवं जी0एस0बी0 आंशिक रूप से किया गया है । संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । जुलाई,2016 तक कार्य पूर्ण करने के लिये संवेदक से शपथ पत्र की मांग की गयी है कि वे समय-सीमा के अंदरी पूरा कर दें ।

श्री सचीन्द्र प्र0 सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसाकि मंत्री जी बता रहे हैं कि मिट्टी कार्य संवेदक द्वारा कर दिया गया है तो किसी भी रोड को देखेंगे कि जब मिट्टी कार्य कर दिया जाता है, मिट्टी दोनों तरफ से काट कर जमा कर दिया जाता है, रोड के किनारे किनारे और सड़क बिल्कुल नहर की तरह हो जाता है, थोड़ा भी वर्षा हुइ ेतो उसमें आवागमन का प्रोब्लीम हो जाता है । माननीय मंत्री कह रहे हैं कि संवेदक से एफिडेविट लिया जायेगा कि जुलाई,16 तक पूरा कर दें लेकिन तत्काल कितने दिनों में उस सड़क को मोटरेबुल करवा देंगें ?

श्री शैलेश कुमार : जुलाई,16 तक एफिडेविट ले रहे हैं बल्कि ले लिये है और उसको जुलाई,16 तक काम को पूर्ण करना है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 260 (श्री राजेश कुमार)

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग ।

यह स्थानान्तरित हुआ है । आज यह स्थगित रहेगा । माननीय मंत्री के पास शायद यह नहीं पहुंचा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 261 (श्री नौशाद आलम)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : महोदय, (1) : स्वीकारात्मक है ।

(2) : प्रश्नाधीन चेंगा नदी पर पुल का निर्माण अपरिहार्य कारणश वर्ष 2015-16 में नहीं किया जा सका है लेकिन वर्ष 2016-17 में पूर्ण कार्य योजना में सम्मिलित कर अगले दो वर्षों में पूरा कर लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : मा0स0,आप का सकारात्मक जवाब है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 262 (श्री समीर कुमार महासेठ)</u>

श्री तेज प्रताप यादव : अध्यक्ष महोदय, खंड 1 : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड 2 : मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल प्रखंड के सरिसवपाही पूर्वी पंचायत के इशहहपुर एवं विहो वुधेश राजकीय नलकूपों का बोरवेल इंट-पत्थर से भरा हुआ है । बोर वेल असफल होने के कारण दोनों नलकूपों को चालू कराना संभव नहीं है ।

श्री राज कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि दो नलकूप थे, दोनों खराब हैं । कुछ तो हमको आश्वासन मिलना चाहिए कि कबतक वहां फिर से चालू हो जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने आपको बताया कि आज उन दोनों नलकूपों की यह हालत है कि उसमें इंट-पत्थर भरे हुये हैं, उनको चालू कराना संभव नहीं है । आप कह रहे हैं तो माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लीजियेगा, अगर संभव होगा तो ।

श्री तेज प्रताप यादव : योजना में यह नहीं है । इसको दिखवा लिया जायेगा ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, दिखवायेंगे क्या ? अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सके तो उसकी माननीय मंत्री जी वैकल्पिक व्यवस्था करा दें ।

श्री राज कुमार महासेठ : दिखवाने का क्या औचित्य है । यह नहीं चलने लायक है ।

श्री सदानन्द सिंह : दिखवाने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं । गलत बात मत कीजिये । वैकल्पिक व्यवस्था की बात है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 263

श्री शैलेश कुमार 1-उत्तर स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल के दोनों तरफ मिलाकर पहुंच पथ की लम्बाई 2 कि0मी0 है। उक्त पथ में कोई बसावट नहीं रहने के कारण इसे राज्य कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है। उक्त पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 7 कि0मी0 की दूरी पर 3x22.5 मीटर आकार का उच्चस्तरीय पुल है। यह डाउन स्ट्रीम में 8 कि0मी0 की दूरी पर स्क्रू पाईल पुल 144 मीटर लम्बाई में निर्मित है। प्रश्नाधीन पुल के संबंध में कार्यपालक अभियंता से टेक्नो फिजिब्लिटी रिपोर्ट की मांग की जा रही है।

श्रीमती लेशी सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय,जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि दोनों तरफ आबादी नहीं है और बगल में पुल है तो काफी दूर पर पुल है और यह मुख्य पथ है जो के. नगर प्रखंड और श्रीनगर प्रखंड को जोड़ने वाली ये पथ ओर पुल है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पथ है और लोगों को अभी एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में जाने के लिए 15 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है,चम्पानगर होकर जाना पड़ता है तो क्या माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहती हूँ कि पुनः इसको देखवाकर और वहां के लोगों की आवागमन की सुविधा के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2016-17 में पुल का निर्माण कराना चाहते हैं?

श्री शैलेश कुमार: अध्यक्ष महोदय,हमने बताया माननीय सदस्य महोदया को कि प्रश्नाधीन पुल के संबंध में कार्यपालक अभियंता से टेक्नो फिजिब्लिटी की रिपोर्ट की मांग की गयी है। इसकी गम्भीरता को समझते हुए हम माननीय सदस्य से भी बाद में बात कर लेंगे।

अध्यक्ष: ठीक है।

श्री आफाक आलम: अध्यक्ष महोदय,यह पुल दो प्रखंडों को जोड़ता है और .....

अध्यक्ष: आपका भी सुझाव है कि पुल बनना चाहिए। माननीय मंत्री जी देखेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 264

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव: महोदय,(1) स्वीकारात्मक है। यह पथ वर्त्तमान Long Term output and performance base road asset maintenance contract के पैकेज संख्या-31 में संधारण हेतु शामिल है एवं पथ अच्छी स्थिति में है। किसी भी पथ के चौड़ीकरण का निर्णय उनके संगत पहलुओं यथा सड़क की स्थिति,यातायात घनत्व,

निधि की उपलब्धता को घ्यान में रखकर किया जाता है। तत्काल इस पथ का चौड़ीकरण कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

श्री मुजाहिद आलमः माननीय अध्यक्ष महोदय,ये जो सड़क है, ये कोचाधामन की लाईफ लाईन है और इसमें इतनी दुर्घटनाएं होती है, इतने लोगों की जान गयी है कि लोग इसको मौत की सड़क कहते हैं और ये वर्ष 2015-16 के कार्य योजना में शामिल है। अधीक्षण अभियंता द्वारा अपने ज्ञापांक 686 दिनांक 1-7-2015 को इसका प्राक्कलन स्वीकृति हेतु भेजा गया। यह वर्ष 2015 के कार्य योजना में शामिल है इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके द्वारा यह आग्रह करता हूॅ कि इस पथ को स्वीकृत करने की कृपा करें।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने आपको विस्तार से बताया है कि पैकेज संख्या- 31 में शामिल है और चौड़ीकरण का फैसला उस पर जो ट्रॉफिक होता है उसका घनत्व देखकर के बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। आपने जो कहा है, पत्र माननीय मंत्री जी को दे दीजियेगा, उसके आधार पर देखेंगे।

श्री मुजाहिद आलमः इस पर बहुत ज्यादा ट्राफिक है,सर और यह कार्य योजना में भी शामिल है।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी दिखवा लीजियेगा। ये कह रहे हैं कि कार्य योजना में शामिल है।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः देखवा लेंगे। इनका यह बात सही है कि वहां काफी ज्यादा कर्व बगैरह है तो दुर्घटना की संभावना रहती है। मगर इसमें भी हर जगह हमलोगों का साईन बोर्ड है वह दिया जाता है मगर दिखवा लेते हैं।

श्री प्रेम कुमारः महोदय,माननीय सदस्य ने कहा है कि मौत का सड़क है। सड़क का नाम जो उन्होंने कहा है कि लोग वहां कहते है कि वह मौत का सड़क है और सरकार कह रही है दिखवायेंगे तो लगातार लोगों की जानें वहां जा रही है, लोग मर रहे हैं महोदय और सरकार दिखवाने की बात कह रही है। हम चाहेंगे माननीय मंत्री जी आग्रह करेंगे..

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय..

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमारः हर चीज में बिजेन्द्र बाबू खड़े हो जाते हैं। अरे,माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं आपको खा-म-खाह खड़ा होने की क्या जरूरत है।

(व्यवधान)

मैं पूरे बिहार का नेता हूॅ,प्रतिपक्ष का नेता हूॅ इसलिए कह रहा हूॅ और महोदय..

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: महोदय,हम कहना चाहते हैं महोदय पहली बार बिहार में मौत का सड़क माननीय सदस्य सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य हैं और उन्होंने मौत की सड़क का चर्चा किये हैं। सरकार 24 घंटे के अन्दर में कोई व्यवस्था कराये ताकि घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका आश्वासन दीजिये।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: महोदय,इतनी दुघर्टना हो रही है मौत का सड़क नाम दिया गया उस सड़क का हम आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री आश्वस्त करें कि एक सप्ताह के अन्दर में इसको ऐसा कर दिया जाये कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार: अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: महोदय,जब इनको करने का समय था तो ध्यान देना चाहिए था पथ बढ़िया बढ़िया बनवाना चाहिए था पथ निर्माण विभाग का तो उस समय तो कुछ किये नहीं और अब प्रतिपक्ष में चले गये हैं तब इनको बिहार का रोड दिखलाई दे रहा है और सरकार में थे तो इनसे कुछ किया ही नहीं।

श्री प्रेम कुमार: महोदय,जब प्रेम कुमार पथ निर्माण मंत्री था उसी के भरोसे नीतीश कुमार का बिहार में दोबारा सरकार आयी थी और बिहार में हमने इतना काम किया था इस मामले में पूरे बिहार में 2005 के बाद सरकार आयी थी तो प्रेम कुमार का और एन0डी0ए0 के हमारे मंत्रियों का योगदान था, हमने बिहार में सड़क बनाने का काम किया।

श्री श्रवण कुमार: अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या- 265

अध्यक्ष: अगर प्रश्नों को जल्दी से निपटने देंगे तो ज्यादा प्रश्न आयेंगे और ज्यादा सदस्य भी संतुष्ट रहेंगे।

श्री शैलेश कुमार: अध्यक्ष महोदय,1-उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सी0एन0सी0पी0एल0 में एल 03-2 के

रूप में अंकित पथ 03 से बैजा पथ पर अवस्थित है। उक्त पुल का कार्य 15 मीटर गुणा 3 मीटर का होगा । उक्त पथ के साथ साथ पुल का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है। तत्पश्चात् इस पर एस0टी0ए0 का अनुमोदन प्राप्त कर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जायेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति के पश्चात् उक्त पथ के साथ प्रश्नाधीन पुल का निर्माण किया जा सकेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या- 266

श्री शैलेश कुमारः अध्यक्ष महोदय,उत्तर स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत राधे मादे दक्षिण टोला से राधे मादे साउथ टोला तक का निर्माण कार्य प्रगति में है जिससे बथना को सम्पर्कता प्रदान हो जायेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोर नेटवर्क एल-03-0-03 से ओक्सा हाजी टोला तक पथ के निर्माण हो जाने पर ओक्सा को सम्पर्कता हो जायेगी। उक्त पथ का डी0पी0आर0 बनाया जाना है। प्रश्नाधीन सम्पर्क पथ बथना से ओक्सा की लम्बाई लगभग डेढ़ कि0मी0 है जिसमें प्रश्न में अंकित निर्मित पुलिया के अलावे 30 मीटर लम्बे पुल की आवश्यकता होगी। यह पथ राज्य कोर नेटवर्क में शामिल नहीं है क्योंकि इनके दोनों छोर के बसावट को उपर वर्णित पथों से सम्पर्कता प्रदान हो रही है। उक्त कारण से प्रश्नाधीन सम्पर्क पथ का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री मनोहर प्रसाद सिंहः पुल बना था तो मंत्री महोदय यह बताना चाहेंगे कि पुल कब बना था?

अध्यक्षः ये पूछ रहे हैं पुल कब बना था। यह थोड़ा भारी प्रश्न है हल्का पुछिये। आपने तो इसमें सम्पर्क पथ की मांग की है।

तारांकित प्रश्न सं0 266 का पूरक ..क्रमशः...

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, पुल बना था, उसी पुल के लिए सम्पर्क पथ की मैंने मॉग की थी । ये बोलते हैं कि बनेगा ही नहीं, क्या-क्या उन्होंने बताया ।

अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि उस पुल से सम्पर्क की वैकल्पिक व्यवस्थाएॅं या वैकल्पिक सड़कें हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : नहीं है । इसीलिए मैंने प्रश्न किया था ।

अध्यक्ष : आप वह प्रश्न पूछिये न कि जो भी व्यवस्था है, लेकिन यह सड़क ज्यादा उपयोगी है !

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : वही तो मैं इसलिये पूछ रहा था कि जब पुल बनाया गया था तो उसी समय ही उनको सम्पर्क पथ बनाना चाहिये । जब सम्पर्क पथ नहीं बना तो उस पुल की जरूरत क्या थी ?

अध्यक्ष : देखवा लीजियेगा सड़क के बारे में ।

श्री शैलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना है...

अध्यक्ष : इसको देखवा लीजियेगा न !

श्री शैलेश कुमार : ठीक है । इसको देखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 267 (श्री सुरेश कुमार शर्मा)

श्री शैलेश कुमार : महोदय, स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि इस पथ की लम्बाई 1.5 कि0मी0 है । इसके निर्माण में लगभग 1 करोड़ 5 लाख रूपये व्यय अनुमानित है। यह पथ स्टेट कोर नेटवर्क में सी0यू0पी0एल0 के क्रमांक- 11 पर अंकित है । इस पथ का सर्वेक्षण कार्य मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना विश्व बैंक सम्पोषित के तहत कराया जा रहा है ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा : अभी तक यह किसी में भी नहीं आया है । मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि यह तो किसी योजना में नहीं है, इसको कबतक बनवायेंगे ? अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी योजना में है तो बताने की कृपा करें ।

श्री शैलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि इस पथ का सर्वेक्षण कार्य हमलोग माननीय मुख्यमंत्री सम्पर्क योजना से करा रहे हैं । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि इसके लिए आशान्वित रहें ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 268 (श्री बशिष्ठ सिंह)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रसूलपुर वितरणी पश्चिम मुख्य नहर के 29 कि0मी0 से निस्सरित है । इसकी कुल लम्बाई 22 कि0मी0 है तथा रूपांकित जल स्त्राव 140 क्यूसेक है । नहर के दोनों तटबंध ठीक हैं तथा नहर में कहीं-कहीं गाद जमा है । ग्रामीणों द्वारा सिंचाई के दौरान बांध को कभी-कभी क्षतिग्रस्त किया गया ।

खरीफ सिंचाई 2015 के दौरान इस नहर में सम्पोषण मद से मरम्मति कराकर नहर के अंतिम छोर तक पटवन कराया गया है । वर्ष 2015 खरीफ सिंचाई में इस नहर के सिंचित क्षेत्र 4 हजार हेक्टेयर के विरूद्ध सिंचाई की उपलब्धि 3990 हेक्टेयर रहा है। करगहर वितरणी भाग गारा चौबे शाखा नहर के 12.50 कि0मी0 से निस्सरित है जिसकी कुल लम्बाई 37.20 कि0मी0 है तथा रूपांकित जल स्त्राव 620 घनसेक है । इसके दोनों तटबंध भी ठीक हैं तथा विगत खरीफ 2015 सिंचाई के दौरान अधिकतम जल स्त्राव 600 क्यूसेक प्रवाहित हुआ । इन्द्रपुरी बराज में जल उपलब्धता की कमी रहने के कारण तातिल व्यवस्था से करगहर वितरणी के अंतिम छोर तक जल उपलब्ध कराया गया। इस वितरणी के खरीफ सिंचाई लक्ष्य 12713 हेक्टेयर के विरूद्ध उपलब्धि 10434 हेक्टेयर रहा है । वर्णित परिस्थिति में प्रश्नाधीन वितरणियों में उड़ाही की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बशिष्ठ सिंह : सर, जो करगहर वितरणी नहर है, उस नहर में करगहर प्रखंड मुख्यालय और थाना मुख्यालय के पास एक तरफ से पी0डब्लू0डी0 सड़क गया है और एक तरफ से गॉंव है । वहॉं पहले से बने हुये कैनाल की चौड़ाई कम है और वहॉं पहले पक्की था, वह टूट गया है । टूटने के बाद करगहर से थोड़ा पहले वहॉं बार-बार तटबंध टूट जाता है, टूटने के बाद वह पानी नदी में चला जाता है और कई गॉंव के किसान का धान बर्वाद हो जाता है । दूसरे तरफ पानी तटबंध से ओवरफ्लो करके पी0डब्लीू0डी0 रोड को पार करते हुए चाट में चला जाता है ।

हम माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहेंगे कि वहॉं पर उसको पक्कीकरण कराया जाय और पक्कीकरण कराकर तटबंध को ठीक कराया जाय । महोदय, वहीं करगहर थाना के सामने 15 वर्ष पहले का एक पुल बना हुआ है, उस पुल का दोनों जो एप्रोच है, आज तक नहीं बना है जिसके चलते आज तक उस पुल पर आवागमन बाधित है । जो करगहर से फुली परसथुआ कुदरा पथ जाता है, जो करगहर का इम्पौर्टेंट

रोड है और उसी रूट से जाना होता है । अंग्रेज के जमाने का बनाया हुआ पुल आज के डेट में ध्वस्त हो चुका है....

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये न !

श्री बशिष्ठ सिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि करगहर का जो तटबंध टूटा हुआ है, वहाँ उसको पक्कीकरण कराया जाय । जो पुल आपका 15 वर्ष पहले से अधूरा है, उसको बनवाया जाय और अंतिम तक पानी पहुंचाने की कृपा की जाय ।

दूसरा है कि रसूलपुर वितरणी में आपका एक सड़क है अगरई डुमरा पथ, उस पथ में डुमरा गाँव से पूरब वह पुल दो वर्ष से टूटा हुआ है, जो पी0डब्लू0डी0 रोड के बीच प्वायंट में है । उस रोड से आवागमन बाधित है । सिंचाई विभाग के पदाधिकारी से भी मैंने कई बार मिलकर कहा लेकिन उसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, मैंने बता दिया कि जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है इरीगेशन पोटेंशियलिटी का, वह मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमलोगों ने 2015 में खरीफ के दौरान किया है और पानी अंतिम छोर तक हमने पहुंचाया । हमने कहा कि 4 हजार हेक्टेयर के विरूद्ध 3990 हेक्टेयर और 12713 हेक्टेयर के विरूद्ध 10434 हेक्टेयर में हमने खरीफ के दौरान इरीगेशन उपलब्ध कराया ।

महोदय, सोन में जो पानी की स्थिति है वह सबको मालूम है । वाणसागर और रिहन्द के माध्यम से हमको पानी मिलता है । अब वहाँ से पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है तो हम तातिल करके इस रब्बी के मौसम में पानी पहुंचा रहे हैं और हमलोग मैक्सिमम जो इरीगेशन पोटेंशियलिटी है, उसका इस्तेमाल करेंगे । हमने साफ बताया कि इसकी मरम्मति की अभी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री बशिष्ठ सिंह : मंत्री जी, जो पुल टूटा हुआ है रसूलपुर में दो साल से.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने प्रश्न में चर्चा की है दोनों वितरणी के उड़ाही एवं पक्कीकरण की, उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया । अब आप जिक्र कर रहे हैं दो पुल की कि पुल क्षतिग्रस्त है, उसकी मरम्मति करायी जाय । उसका तो आपने इस प्रश्न में जिक्र किया नहीं है, इसके लिए अलग से लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दीजियेगा, देखवा लेंगे ।

श्री अशोक कुमार(208) : महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल किया है उड़ाही का और तटबंध के निर्माण का, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि तटबंध टूटा हुआ नहीं है । माननीय सदस्य और माननीय मंत्री के बात में विरोधाभास है, इसलिये हम आपका संरक्षण चाहते

हुये, माननीय सदस्य नये सदस्य हैं, आपका संरक्षण चाहते हुये, इस बात की जॉंच कमिटी से करा ली जाय कि तटबंध टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है, मिट्टी भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है, इसकी जॉंच करा ली जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अशोक जी, यह तो पूरा प्रश्न जो है वितरणी के उड़ाही एवं पक्कीकरण से संबंधित है तो आप तटबंध पर कहॉं चले गये !

श्री अशोक कुमार(208) : अध्यक्ष महोदय, तटबंध का निर्माण कार्य, ये वहीं के सदस्य हैं....

अध्यक्ष : इस प्रश्न में तटबंध का निर्माण कहॉं है ? आप तीसरा ऐंगल दे रहे हैं । प्रश्न संख्या 269 ।

श्री अशोक कुमार(208) : नहीं अध्यक्ष महोदय, सवाल हम पढ़ते हैं, सवाल यह है कि रसूलपुर वितरणी एवं करगहर वितरणी का दोनों तट क्षतिग्रस्त है....

अध्यक्ष : आप प्रश्न पढ़िये कि क्या सरकार रसूलपुर वितरणी एवं करगहर वितरणी का उड़ाही एवं पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ? इसमें तटबंध कहॉं से आ गया !

श्री अशोक कुमार(208) : उसके उपर पढ़ा जाय कि क्या सवाल किये हैं । मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत रसूलपुर वितरणी एवं करगहर वितरणी का दोनों तट क्षतिग्रस्त हो गया है....

अध्यक्ष : वितरणी का तट है न ! इसमें तटबंध कहॉं से आ गया ?

श्री अशोक कुमार(208) : वितरणी का तट, वही कह रहे हैं और माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि क्षतिग्रस्त नहीं है...

अध्यक्ष : श्री हरिनारायण सिंह, प्रश्न संख्या- 269 ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, माननीय मंत्री महोदय का जो बयान आया है, वह झूठा बयान है, सही बातों को उन्होंने नहीं कहा है, वितरणी की मरम्मती की बात कही गई है । माननीय मंत्री जी इसकी जॉच कराकर के इसका समाधान करावें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इसको देख लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-269(श्री हरिनारायण सिंह,स0वि0स0)

श्री शैलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 3 कि0मी0 है, जिसे वर्ष 2008-09 में मुख्यमंत्री ग्राम्य सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित किया गया था । इस पथ की वास्तविक रूप से कार्य समाप्ति की तिथि 18.09.09 है । 5 वर्षीय रख-रखाव की अवधि समाप्त हो चुकी है । यह पथ नई अनुरक्षण नीति के तहत श्रेणी-2 में है । संसाधन के उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या अगले वित्तीय वर्ष में इस जर्जर सड़क को क्या जीर्णोद्धार करा देंगे ?

श्री शैलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वरिष्ठ भी हैं और हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं, हमने जवाब दिया कि संसाधन की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी फिर भी इसको हम देख लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-270 (श्री अभय कुमार सिन्हा,स0वि0स0)

श्री शैलेश कुमार : महोदय, यह आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन धेजन गांव के धेजन पाई बिगहा-मखदुमपुर पथ से एकल सम्पर्कता प्रदान कर दी गई है। प्रश्नाधीन पथ के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचराधीन नहीं है।

महोदय, एकल सम्पर्कता प्रदान कर दी गई है उस गांव को ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूपसपुर धेजन में पथ पर पुल के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति 8 करोड़ 23 लाख रू0 से बनायी गयी है और पुल बनकर के तैयार हो चुकी है । पुल पहुॅच पथ धेजन तक नहीं होने के कारण पुल की उपयोगिता नगण्य है, न के बराबर है । तकरीबन 1100 मीटर पुल से धेजन तक का पथ का निर्माण हो जाता है, हम महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि 8 करोड़ 23 लाख रू0 के लागत से जो पुल बनी, उसमें बहुत सारा रूपया बचा हुआ है पुल बनने के बाद भी महोदय, जिससे 1100 मीटर पहुॅच पथ का निर्माण करायी जा सकती है ।

अध्यक्ष : इसको देखवा लीजियेगा, कह रहे हैं कि पैसा बची हुई है ।

प्रश्नोत्तर-काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हैं, उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

अध्यक्ष : आज दिनांक 02.03.2016 के लिए कुल 5 कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना निम्नलिखित माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई है । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद, माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका, माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा एवं माननीय सदस्य श्री व्यासदेव प्रसाद ।

माननीय सदस्यगण, आज बिहार विधान सभा में वित्तीय कार्य 2016-17 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार का उत्तर निर्धारित है । साथ ही दिनांक 28.03.2016 को गृह विभाग के अनुदान की मांगों पर सदन में विचार-विमर्श होने का कार्यक्रम भी निर्धारित है । माननीय सदस्य, उक्त अवसरों पर इन विधि-व्यवस्था के विषयों को उठा सकते हैं । अभी उपर्युक्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, दिन-दहाड़े सिवान में गोली चली है, बिहारशरीफ में लूट हुई है और हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा बढ़ते अपराध एवं पूरे राज्य में कानून का राज खत्म हो गया है । अपराध लगातार महोदय बढ़ रहा है, दिन दहाड़े सिवान में 17 लाख रू0 लूटा गया है, लोग घायल हो गये हैं । इस तरह पूरे राज्य में कानून का राज समाप्त हो गया है, जनता भगवान भरोसे है । बिहारशरीफ में लूट हुई है......

अध्यक्ष : शून्य-काल । माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह ।

श्री प्रेम कुमार : इतना गंभीर मामला है और इसपर हम सरकार से जवाब चाहते हैं । राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, आपके ही सदस्य का शून्य-काल है ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, इसपर सरकार से जवाब दिलवाया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक ।

श्री अशोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, हम के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का एक वक्तव्य छपा है कि कमीशन का पैसा सी0एम0 हाऊस जा रहा है । हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि या तो श्रीमान् जी साक्ष्य उपलब्ध करायें या सदन में माफी मांगे ।

अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

श्री अशोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान है । ये या तो साक्ष्य उपलब्ध करायें या सदन के सामने माफी मांगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह, शून्यकाल ।

शून्य-काल

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, ''कैमूर जिलान्तर्गत सोन नहर से निकली गाराचौबे, सथलुआ तथा करगहर नहरों में कम पानी की मात्रा से रब्बी की अरबों रूपये की फसल सूखने के कगार पर है, जिससे किसान परेशान है । उक्त नहरों में पानी की मात्रा बढ़ाकर खेतों की सिंचाई की मांग करता हूँ । ''

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि सिंचाई के कम में किसानों के द्वारा नहरों को बाधित कर दिया गया । महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ, सरकार को जानकारी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि माननीय सदस्य श्री वशिष्ठ जी ने करगहर माईनर का सवाल उठाया था, करगहर माईनर से हमारे इलाके का 10 पंचायतों का पटवन होता है । वह नहर सरकार के हाथ में नहीं रह गई है, वह नहर इलाके के असामाजिक तत्वों के हाथों में चली गई है । नहर के डिजाईन के विपरित महोदय जहां मन में आ रहा है, वहां पाईप लगाकर के ....

अध्यक्ष : ठीक है । वह सूचना भी आप सरकार को दे दे इस सूचना के साथ ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा करगहर माईनर के तरफ महोदय, जहां डिजाईन के विपरीत काम किया गया है, उसको तोड़वाया जाय और पानी की व्यवस्था करके किसानों के खेतों में पानी दिया जाय।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री ललन पासवान ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, रोहतास, कैमूर जिला अन्तर्गत नौहट्टा, रोहतास तिलौथू, चेनारी, शिवसागर, सासाराम, रामपुर, भगवानपुर और चैनपुर चॉद के वनवासी आदिवासी पशु नदियों की सड़ी चुआड़ी की पानी पीने को मजबूर हैं ।

सरकार से मांग करते हैं कि इन प्रखंडों में सभी गांवों में पीने की पानी जल्द व्यवस्था करें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार जब से सदन में आया हूँ, लगातार यह बात कह रहा हूँ.....

श्री प्रेम कुमार : माननीय सदस्य ने सही कहा महोदय, दोनों जिला में महोदय पानी का काफी संकट है । काफी गंभीर सवाल महोदय है.....

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री ललन पासवान तख्ती लेकर सदन के वेल में आ गये)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललन जी, आपकी बात का ज्यादा वजन है उस तख्ती से । उस तख्ती को हटा दीजिए, आपकी बात का ही ज्यादा वजन है ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, पानी का मामला है, आपसे आग्रह है कि सरकार इसपर संज्ञान ले और संज्ञान लेकर के सरकार इसपर अवलिम्ब कार्रवाई करे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, 26 दिसम्बर को दरभंगा में ए0के047 से दो इंजीनियरों की हत्या कर दी गयी, अभी तक मुख्य अभियुक्त फरार है । सरकार जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करे और इंजीनियरों के परिजनों को 20-20 लाख रू0 मुआवजा दे ।

अध्यक्ष महोदय, मिथिला जो है शांति का प्रतीक रहा है और अभी वहां ए0के047 चल रहा है । दो महीने के लगभग हो गया है अध्यक्ष महोदय........

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, शून्य-काल में महोदय नियम और प्रक्रिया है, भाषण देने का प्रक्रिया है या पढ़ने का प्रक्रिया है, यह मैं जानना चाहता हूँ ? ये पुराने मेम्बर हैं, सारे सदस्य इसपर भाषण कर रहे हैं । इनको भाषण देने से काम चलने वाला है, ये तथ्य को रखने का काम करें ....

श्री संजय सरागवी : महोदय, वहां ए0के047 चल रहा है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं हमलोग, दो-दो इंजीनियरों की हत्या हो गई, अभी तक सरकार का कोई आदमी इंजीनियर के पास नहीं गया है । इसलिए ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार सिंह, अब नीरज जी को पढ़ने दीजिए ।

श्री श्रवण कुमार : महोदय, जो नियम प्रक्रिया है, सरकार उसको गंभीरता से लेती है लेकिन बगैर नियम एवं प्रक्रिया का ये पुराने सदस्य हैं और इस तरह का सवाल उठायेंगे महोदय तो सरकार इसकी जवाबदेही नहीं लेगी । सरकार जवाबदेही लेगी अगर कोई माननीय सदस्य नियम एवं प्रक्रिया के तहत कोई सवाल उठा रहे हैं ।

श्री नीरज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिला के सौर प्रखंड स्थित हरकुट्टा मुसहरी गांव में विगत दिनों महादलित परिवार के सदस्य के साथ दाह संस्कार के समय दबंगों द्वारा कई महादलितों का टांग-हाथ तोड़ दिया गया । मैं अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, अतिगंभीर मामला है । महोदय, महादलित का सवाल है, महादलित लोग दाह संस्कार के लिए खेत में गये थे लेकिन मेढ़ पर दाह संस्कार के नाम पर महादलितों को पीटा गया, हाथ-पांव तोड़ दिया गया । महोदय, मामला दर्ज है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभीतक नहीं हुई है, केस का सुपरीवजन हुए 15 दिन बीत गया, सारी प्रक्रिया हो गयी है लेकिन पता नहीं किनका संरक्षण मिला हुआ है कि अभीतक किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है । महोदय, महादलित का सवाल है और महादलितों के साथ अन्याय हो रहा है । महादलित मुसहर को उजाड़ा जा रहा है....

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर वही सवाल उठा रहा हूँ कि शून्य-काल के लिए नियम और प्रक्रिया विधान सभा में बनी हुई है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं, अगर कोई नये सदस्य सवाल उठाते तो वह कुछ क्षम्य के लायक है । ये पुराने मेम्बर हैं, भाषण दे रहे हैं शून्य-काल में ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

(व्यवधान)

एक मिनट खेमका जी । देखिए, सदन के सभी माननीय सदस्यों को स्पष्ट होना चाहिए....

(व्यवधान)

ललन जी, माननीय सदस्य जानते हैं कि शून्य-काल में कोई अत्यावश्यक तुरंत हुई घटना के संबंध में बात उठाते हैं और आप खुद कह रहे हैं कि पुरानी समस्या है.... व्यवधान.... आप पूरी बात तो सुन लीजिए, जहां तक शून्य-काल के संबंध में नियम और प्रक्रिया की बात है तो सामान्य रूप से यही परम्परा है कि इसमें आप सिर्फ आपने जो लिखित सूचना दी है, उसी को पढ़ा जाता है । सदस्य चूंकि अपनी बात कहना

चाहते हैं तो हम थोड़ा और समय दे देते हैं लेकिन नियम यही है कि सभी को सिर्फ अपनी सूचना देनी है ।

(इस अवसर पर मा0 सदस्य श्री ललन पासवान अपने सीट पर चले गये)

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णियां जिला के जलालगढ़ सी0एम0आर0 गोदाम में पड़ा हुआ दो हजार क्विंटल सरकारी खाद्यान्न सड़ गया है, जिसकी कीमत लगभग पांच करोड़ रूपया है । जिला प्रशासन सभी प्रखंड स्थित एफ0सी0आई0 के गोदामों में सड़े चावल भेजकर पी0डी0एस0 में इसे खपाना चाहती है ।

अध्यक्ष महोदय, तीन हजार क्विंटल चावल पूर्व में भी सड़ गया था, वह गरीबों के बीच पी0डी0एस0 के माध्यम से जिला प्रशासन ने बांटने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि सरकार तुरंत सड़े हुए चावल की आपूर्ति पर रोक लगाये एवं इसकी जांच कराकर जो जिला के पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं, उनको दंडित किया जाय ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पकड़ीदयाल प्रखंड परिसर में ई0 किसान भवन का निर्माण कार्य जनवरी,2015 में शुरू हुआ, जिसे दिसम्बर,2015 में पूरा होना था, परन्तु राशि के अभाव में अपूर्ण है, जिसे पूर्ण कराने की मांग मैं सदन से करता हूँ ।

श्रीमती भागीरथी देवी : हुजूर, मेरी बात गौर से सुनी जाय । पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड रामनगर नगर पंचायत में वर्ष 2010 से अबतक सस्ते दर पर मार्कस लाईट, ट्रैक्टर, सोलर, डस्टबीन इत्यादि क्रय किया गया और इसका दाम दुगुना, तिगुना लगाकर बिल बनाया गया लेकिन वह काम नहीं कर रहा है

अध्यक्ष : क्या आप जांच कराना चाहती हैं ?

श्रीमती भागीरथी देवी : जांच करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्रीमती भागीरथी देवी : जांच करा दिया जाय कि आखिर जो सामान खरीदा गया, वह काम क्यों नहीं कर रहा है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी ।

श्रीमती भागीरथी देवी : महोदय, जांच इसका भी होना चाहिए कि बेसी-बेसी पैसा लगाकर, दुगुना पैसा लगाकर कम दर का सामान क्रय किया गया । महोदय, इसमें घोटाला हुआ है...

(व्यवधान)

मुझे बोलने दिया जाय, नहीं तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे....

अध्यक्ष : आप उधर क्यों बोल रही हैं, आप आसन की ओर बोलिए ।

श्रीमती भागीरथी देवी : महोदय, माननीय सदस्य को समझाया जाय । नये-नये सदस्य आ गये हैं, पहले इन लोगों को समझाया जाय । कोई भी पुराने सदस्य जब खड़े होकर बोलने लगते हैं तो उधर से भी बोलना शुरू कर देते हैं । यह कोई बात हुई ? पहले इन लोगों को समझाया जाय । पहले नये सदस्य को समझाया जाय ।

अध्यक्ष : श्री विनय बिहारी जी । आप बोलिए ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, योगापट्टी प्रखंडान्तर्गत नवलपुर निवासी श्री सनोज प्रसाद के 6 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार की निर्मम हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गयी । सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि अपराधियों को कड़ी सजा व पीड़ित परिवार को पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाय ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत मनियॉ रेल गुमटी के समीप महादेवपुर का प्लाई तथा पेंट दूकानदार लखन अग्रवाल की निर्मम हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गई, अभीतक एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है ।

अत: अपराधियों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार सिन्हा ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बेलगाम अपराधी घूम रहे हैं । 3 फरवरी को हत्या की गयी है और अभीतक एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है । कुर्की जप्ती भी नहीं हुआ है, सरकार की ओर से इसका जबाब चाहिए । अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मैं वेल पर जाउंगा क्योंकि लखन अग्रवाल के हत्यारा को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया....

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह सदन के वेल में आ गये)

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार सिन्हा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25.02.2016 को लखीसराय नगर व्यवसायी रतनलाल बंका के घर भीषण डकैती सहित लखीसराय में छ: डकैती और

दिनदहाड़े गणेश साव की हत्या से लोग दहशत में हैं । अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

अत: अपराधियों की गिरफ्तारी और व्यवसाईयों की सुरक्षा की मांग करता हूँ ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह अपने सीट पर चले गये)

अध्यक्ष महोदय, 6-6 डकैती हो चुका है और गणेश साव की हत्या दिनदहाड़े कर दी गयी, उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई । जिसका नाम दिया गया, उसकी लीपापोती करके, खानापूर्त्ति करके निकाल दिया गया, अत: उसपर कार्रवाई हो....

अध्यक्ष : श्री तारकिशोर प्रसाद ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, लगभग तीन वर्षों से सदर अस्पताल कटिहार में स्थापित आई0सी0यू0 विशेषज्ञ चिकित्सक के अभाव में बंद है, जिससे संघातिक रोग के मरीज असमय काल कलवित हो रहे हैं । कई बार ध्यान आकृष्ट करने के बाद भी आजतक आई0सी0यू0 चालू नहीं हो पा रहा है ।

अत: सरकार अविलम्ब विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करे ।

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला समाहर्त्ता के हाउस गार्ड अनिल कुमार और उसके दो साथियों के द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया । सरकार उस दोषी को गिरफ्तार करे, उसे बरखास्त करें और उस पीड़िता को 10 लाख रूपया मुआवजा सरकार दे ।

अध्यक्ष महोदय, जो अल्पसंख्यक समाज की बच्चियां हैं, उनके दरवाजे से उठाकर पुलिस ने रेप किया है मसुरी के खेत में और उसके बाद वह रिवाल्वर गोली सहित लेकर भाग गया अपने घर नालन्दा । जब पुलिस पकड़ने गयी तो पुलिस पर फायरिंग किया गया और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई । यहां के एस0पी0 ने उसे सस्पेंड किया है जबकि सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है । ऐसे पुलिस पदाधिकारी को अविलम्ब बर्खास्त किया जाय ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, गोपालगंज सहित पूरे बिहार में सर्वशिक्षा अभियान के तहत 2009-10 में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रखंड नियोजन समिति द्वारा किया गया था। मूक, बधिर, अंधे एवं मंद बुद्धि बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत शिक्षित करने हेतु इन कोटियों के प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाय। महोदय, यह बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है और मेरे प्रखंड में केवल 25 विशेष प्रशिक्षित शिक्षक हैं। 2010 के बाद इनकी नियुक्ति नहीं हुई और ये जो कोटि के बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाला बिहार के किसी विद्यालय में नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह होगा महोदय कि इस मामले को जरा गंभीरता से लिया जाय।

श्री विद्यासागर केशरी : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के हल्हलिया पंचायत में मांस फैक्ट्री के चलते पर्यावरण से लेकर मानवीय जीवन पर भी गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। फैक्ट्री के 2 कि0मी0 के आसपास के लोग पलायन कर रहे हैं। बावजूद सरकार इसे प्रतिबंधित करने के बजाय वित्तीय अनुदान देकर प्रोत्साहित कर रही है। महोदय, वहां जो फैक्ट्री लगी हुई है उसमें 16 अप्लीकेशन और पड़े हुए हैं, तीन-तीन की अनुशंसा की गयी है। 10-15 कि0मी0 के रेडियस में जो भी गर्भवती महिला रहती है उनको भोमेटिंग की शिकायत आ रही है। मैं सदन के माध्यम से सरकार का घ्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम ये फैक्ट्रियाँ बंद हों उसके क्षेत्र में।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना। श्री नवाज आलम।

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

श्री प्रेम कुमार : महोदय, विजय सिन्हा जी सहित कई माननीय सदस्यों ने राज्य में बढ़ते अपराध, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। हत्या अपहरण, बलात्कार की घटनाएं लगातार घट रही है, सरकार के स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कई सदस्यों ने इन मामलों को उठाया है, इसपर सरकार का जवाब हो। अपराध बढ़ रहा है, अपराध रूक नहीं रहा है।

(व्यवधान)

मो0 नवाज आलम, श्री सुदामा प्रसाद एवं अन्य तीन सभासदों की घ्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

मो0 नवाज आलम : महोदय, सोन नहर प्रणाली से राज्य के आठ जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की गयी थी, जिसमें नहरों को पानी सोन नदी द्वारा दिया जाता है। सोन नदी के सूख जाने के फलस्वरूप नहर में पानी आना बन्द हो गया है। सोन नहर के पानी का वितरण करने के समय राज्य हित में कदवन जलाशय का निर्माण का विकल्प राज्य को मिला था जो अब तक नहीं किया गया है। फलस्वरूप हजारों एकड़ रबी की फसल सिंचाई के अभाव में सूख गये हैं।

अत: जनहित में नहरों में पानी देने की व्यवस्था के लिए कदवन जलाशय का निर्माण कराने हेतु हम सदन के माघ्यम से सरकार का घ्यान आकृष्ट करते हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सोन नहर प्रणाली के अंतर्गत वाणसागर एकरारनामा के तहत रिहण्द तथा वाणसागर जलाशय से क्रमश: 1.00 एम0ए0एफ0 तथा 2.59 एम0ए0एफ0 पानी मिलता है। वाणसागर एकरारनामा के तहत रिहण्द जलाशय के जल के वितरण हेतु ज्वाइंट ऑपरेशन कमिटी की अनुशंसा के अनुसार इस वर्ष 1.40 एम0ए0एफ0 पानी मिलना था जिसके विरूद्ध सोन के जल ग्रहण क्षेत्र में कम वर्षापात के कारण अबतक 0.43 एम0ए0एफ0 पानी मिला है। वाणसागर जलाशय से 1.00 एम0ए0एफ0 के विरूद्ध अब तक 0.97 एम0ए0एफ0 जल प्राप्त हुआ है। तालित की व्यवस्था के तहत नहरों के अंतिम छोड़ तक पानी पहुंचा कर सोन बेसिन के कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। कदवन जलाशय योजना के निर्माण के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। यह योजना वर्ष 1987 में भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा गया था। योजना अभी भी केन्द्रीय जल आयोग में स्वीकृति हेतु लंबित है। इस योजना के केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार से स्वीकृति हेतु विभाग प्रयत्नशील है।

मो0 नवाज आलम : महोदय, आपको जनहित में कोई मतलब नहीं है, केवल फोटो खिंचाइयेगा। महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि किसानों के हित को देखते हुए कब तक राज्य सरकार इस जलाशय का निर्माण करायेगा, अगर करायेगी तो उससे किसानों का बहुत भला होगा। महोदय, वहां लगभग ढाई हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही साथ किसान का- लगभग 8 जिले में किसानों का भला होनेवाला है और उन समस्याओं को सदन में उठाने का मौका मिलता है तो विरोधी दल द्वारा लगातार ऐसे जनहित के मामले को बाधित किया जाता है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हर जिले में किसान सिंचाई के अभाव में, नहर के अभाव में लगातार वहां पर भूखमरी के शिकार हो रहे हैं,

सूखा होने के कारण किसान मरने की अवस्था में है। इसलिए ऐसे मौके पर दुर्भाग्य है इस सदन का कि तमाम विरोधी पार्टी इस तरह के सदन के मामले को, जनहित के मामले को उठाने में रोक रहे हैं।

टर्न-10/अशोक/02.03.2016

(व्यवधान)

श्री रामदेव राय, स.वि.स. से प्राप्त घ्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार(खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय ।

श्री रामदेव राय : "बिहार राज्य में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 30(तीस) लाख क्विंटल था, जिसमें लगभग 25 प्रतिशत ही धान अधिप्राप्ति हुआ है, जिससे किसान बिचौलियौं के हाथों धान बेचने पर मजबूर हैं । इतना ही नहीं पैक्स के माध्यम से भी किसानों का दोहन हो रहा है । मुख्य सचिव के पत्रांक -9071, दिनांक 04.12.2015 के द्वारा पैक्स को 90 प्रतिशत एवं एस.एफ. सी. को 10 प्रतिशत धान लेने का निदेश था जिसका अनुपालन नहीं हुआ है।

अत: दिनांक 31.03.2016 तक लक्ष्य के अनुरूप धान की अधिप्राप्ति कर किसानों को राहत देने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

(व्यवधाान जारी)

श्री श्रवण कुमार : खरीफ विपणन मौसम 2015-16 हेतु 7697 पैक्स/व्यापार मंडल, 100 बिहार राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र ने 160 सी.एम.आर. केन्द्र खोले गये हैं । किसानों की सुविधा के लिए किसानों का ऑनलाईन निबंधन किया गया है एवं अब तक 19,32,390 किसानों का बैंक खाता के साथ विवरणी वेबसाईट पर उपलब्ध है । धान अधिप्राप्ति बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने हेतु प्रति किसान अधिकतम 100 क्विंटल की सीमा निर्धारित की गई है। राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी अधिप्राप्ति व्यवस्था हेतु सामान्यत: किसानों का धान पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से ही क्रय करने का निर्णय है

अत्यन्त ही विशेष परिस्थिति में वैसे किसान जिनका पैक्स में किसी कारणवश धान बेचने में कठिनाई हो, वैसे मामले में अनुमंडल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर ही बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा धान का क्रय किया जाना है । दिनांक 01.03.2016 तक पैक्स के द्वारा 7,97,398.39 मे0 टन धान खरीदा गया है जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है । बिहार राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र द्वारा 2,119 मे0 टन कुल 7,99,517 मे0 टन धान का क्रय किया गया है । धान की मिलिंग पैक्स के द्वारा कराकर बिहार राज्य खाद्य निगम को किया जाना है । अब तक कुल 1,98,793 मे0 टन चावल प्राप्त किया गया है । जबकि विगत वर्ष में मात्र 1,25,767 लाख मे0 टन प्राप्त हुआा था । किसानों से क्रय किये गये धान के मूल्य के भुगतान हेतु कुल 905 करोड़ रूपए का सी.सी. लिमिट पैक्स को दिया गया है जिससे 683 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है एवं प्राप्त सी.एम.आर. के विरूद्ध बिहार राज्य खाद्य निगम के द्वारा पैक्स को 342.22 करोड़ रूपए का भुगतान हुआ है । इस प्रकार किसानों को क्रय किये धान का मूल्य तुरन्त ही RTGS/NEFT के माध्यम से किया जा रहा है ।

किसानों को भुबतान की समस्या नहीं हो इसके लिए 1 हजार 300 करोड़ रूपए का सी.सी. लिमिट पर राज्य सरकार की गारंटी 31 मार्च 2016 तक पूर्व में ही दिया गया है इसके अतिरिक्त 2000 करोड़ का सी.सी. लिमिट पर राज्य सरकार की गारंटी 31 मार्च 2017 तक के लिए दी गयी है। इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान की पुख्ता व्यवस्था की गयी है । जबकि केन्द्र सरकार से विगत वर्ष की अधिप्राप्ति धान के समतुल्य सी.एम.आर. का 2056 करोड़ रूपये कर भुगतान केन्द्र सरकार के द्वारा नहीं कया गया है एवं दावा केन्द्र सरकार में लंबित है । वर्त्तमान वर्ष में कम वर्षा होने के कारण उत्पादन में कमी हुई है फिर भी सरकार किसानों की सुविधा हेतु पारदर्शी व्यवस्था के तहत पैक्स/व्यापार मंडल के माघ्यम से धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है ।

(व्यवधान)

श्री रामदेव राय : महोदय, व्यवस्था को बदलने की कृपा की जाय । यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है । विरोधी पक्ष के लोग भी ये सवाल उठाते रहे हैं, अभी सदन में

घ्यानाकर्षण के जरिये यह सवाल आया है- ये लोग किसानों के कितने बड़े दुश्मन हैं कि किसानों की हित की बात को न तो सुन रहे हैं और न समझने के लिए तैयार हैं तो मैं सरकार से आग्रह करता हूॅ कि जो ये विस्तृत जवाब दिये हैं उसका लिखित मुझे भी मिल जाय तब मेरा पूरक जवाब सन्निहित किया जाय- मेरा पूरक यह है कि पैक्स को ये एक मात्र अधिकृत किये हैं, आज 2 तारीख बीत रहा है, मात्र 28 दिन बचे हुये हैं 30 लाख टन धान खरीदने के लिए बहुत कम समय बचा है जो पैक्स के जरिये सम्मव नहीं है, दूसरी ओर पैक्स किसानों को ब्लैक मेलिग कर रहा है, किसानों को अपने पैक्स के दुकानों में लेने में आना-कानी करता है, कभी कहता है कि मिक्स है, इसको साफ करके दो, कभी कहता है कि कल आओ, कभी कहता है कि परसों आओ, कम्पीटिशन तो है नहीं । पहले मुख्य सचिव के जरिये एक पत्र दिया गया था जिसमें 10 प्रतिशत धान एफ. सी.आई. के जरिये खरीदने का था, इस बार वह भी बंद है, इस बार उसका मोनोपॉली है, इसलिए मैं यह नहीं चाहता हूॅ कि पैक्स नहीं खरीदे,पैक्स के जरिये गांव में, प्रखंड में, प्रखंड में पहले भी ऐसी व्यवस्था थी कि प्रखंड मुख्यालय में धान अधिप्राप्ति के लिए क्रय केन्द्र था । इस बार वह भी नहीं है, तो मैं समझता हूॅ कि इससे सरकार को भारी नुकसान है, नुकसान एक यह है कि पांच प्रतिशत राजस्व की जो प्राप्ति होती है, अगर धान की अधिप्राप्ति की लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है तो सरकार को घाटा होता है, इसलिए लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए सरकार क्रय केन्द्र को बढ़ावे, एफ.सी. आई. को खरीदने के लिए दे और पैक्स पर थोड़ा लगाम लगावे, कारण बिचौलियों से ताल-मेल कर किसानों को लौटा देता है और बिचौलियों कुछ कम कीमत पर धान ले लेता है । दूसरी ओर पैक्स में यह भी है कि पांच किलो अनाज प्रति क्विंटल वह ज्यादा लेता है, दूसरी ओर 1400 रूपये के बदले, 1410 रूपये के बदले 1200 रूपया वह पेमेंट करता है यह किसानों को नुकसान हुआ । किसानों को राहत मिलनी चाहिए, राजस्व वृद्धि सरकार को जायेगा । किसान को कोई लाभ नहीं होगा । किसानों को पूर्व की भांति अगर ये बोनस देती है तो किसान मजबूर होगा पैक्स में देने के लिए, सरकार के हाथ बेचने के लिए तो बिचौलियों का व्यापर बंद जो जायेगा । इसलिए सरकार से आग्रह है कि बिचौलियों को बंद कीजिए और क्रय केन्द्र को बढ़ाते हुये, सरकार के राजस्व में वृद्धि कीजिए ।

श्री श्रवण कुमार : जो सुझाव दिये गये हैं उस पर सरकार पूरा घ्यान रखेगी, किसानों को किसी भी कीमत पर दिक्कत नहीं होने देगी- मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूॅं ।

श्री रामदेव राय : ठीक है ।

(व्यवधान जारी)

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

श्री श्रवण कुमार : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन निमावली के नियम-287(3) के तहत् नियम समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूॅं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

अंतराल के बाद

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष। : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

विधायी कार्य लिए जायेंगे ।

माननीय सदस्यगण , वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय- व्ययक पर सामान्य विमर्श कल दिनॉक 1 मार्च 2016 से जारी है और जारी रहेगा । आज सरकार का उत्तर भी होना है जो 3 बजे से होगा । एक घंटे का विमर्श के लिए समय है और लगभग 7-8 लोगों को बोलना है इसलिए समय का ख्याल रखेंगे । माननीय सदस्य श्री इलियास हुसैन ।

श्री मुहम्मद इलियास हुसैन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका एहसानमंद हूँ । आज बजट के सिलसिले में मुझे बोलने का आपने मौका दिया है शुक्रिया । साथ ही, वजीरेआला जनाब नीतीश कुमार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ चूँकि इनके नेतृत्व में इनके कैबिनेट ने 2016-17 का बेहतरीन बजट पेश किया जो गरीबों, किसानों एवं समस्त बिहार के हित में है । पुन: मैं वित्तमंत्री जनाब सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पानी पी पी करके सदन में बजट को विस्तार से पेश किया और फिर पानी पिला पिला कर विपक्ष के गलत मनसूबें को ध्वस्त किया । महोदय, सरकार ने राज्य का बजट का आकार 2016-17 में 1 लाख 44 हजार करोड़ रुपये रखा है जो अभूतपूर्व है , अपने आप में बेमिसाल है । कम्पैक्ट है । मैं इसका स्वागत करता हूँ । विपक्ष के सम्मानित सदस्य ने बजट पर भाषण देने के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आलोचनाओं की झड़ी लगा दी और बजाप्ता इसमें पूछा कि इसमें नया क्या है ? पढ़ लिखे साथी काबिल दराज अनुभवी । महोदय, इस बजट में इसका आकार नया है इसका आगाज नया है । इस बजट में 7 निश्चय माननीय मुख्यमंत्री के सपने के रुप में आया है इसकी जितनी सराहना की जाय वह बहुमूल्य है । जनाब इसमें प्लाटोज दी रिपब्लिक की सार नयी है इस बजट में और इसको अध्ययन करने की जरुरत है इसमें सुकरात की कल्पना की झलक नयी है 320 बी0सी0 ग्रीस के विद्वानों जैसे सिफैलस थिरेसीमेकस, पोलीमाकर्स, ग्लाउटंस के विचार सन्निहित है । इस विचार को पढ़िये और रामचरितमानस के चौपाईयों की तरह आनंद लूटिये । जितना अध्ययन करेंगे उतना पाईयेगा । नीतीश जी के बजट एवं 7 निश्चयों के बारे में क्या कहना है जरुरत है इसका अध्ययन और ईमानदारी से पार्टी से ऊपर उठ कर हजरत गौर फरमाने की जरुरत है । हुजूर, आज से 450 साल पहले इसी धरती पर सरजमीने हिन्दुस्तान पर

शेरशाह की पैदाईश हुई जिसने कल्पना की और सड़कें बनायी गांव, कस्बों ,प्रान्तों और शहरों को जोड़ा ,कुएं खोदवाए और पानी की व्यवस्था की । जगह जगह वृक्ष लगवाये। छांह का इंतजाम किया । शेरशाह ने सिंचाई को भी नहीं छोड़ा । उसका एग्जाम्पल है, उसका उदाहरण हरिद्वार -रुड़की नहर आज भी विद्यमान है । डाक घोड़े के जरयि डाक की व्यवस्था कायम की । वह आज याद है । सबको याद है । महोदय, आज बिहार विकास के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश जी का जोड़ नहीं । इस कायनात में हजरत गौर फरमायेंगे इस कायनात में कुदरत का बेहतरीन करिश्मा हैं नीतीश कुमार । आप समझो नीतीश कुमार । वह निहायत ही बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं बिहार का सिर्फ इलियास हुसैन का नहीं आप तमाम लोगो के लिए , बिहारवासियों के लिए । महोदय, नीतीश के विकास की गति को भारत सरकार की नीति आयोग ने भी स्वीकार किया । 17.6 प्रतिशत की दर से पूरे देश में सबसे तेज गति से बिहार विकास कर रहा है । यह किसका ओपीनियन है ? नरेन्द्र मोदी जिस संस्था के अध्यक्ष हैं । बयान रोज नहीं पलटता बड़े लोगों का, उसको प्रोलौंग करना चाहिए । उसको जिन्दा रखना चाहिए । हजरत, भारत सरकार के नाइन्साफी को देखिये , कैसा सौतेला व्यवहार है ? हमने अपने जीवन में नही देखा है । हम भी सन् 1980 से इस विधान सभा में हैं । जनाब , इन्दिरा आवास में इस सरजमीन पर केन्द्रांश का 75 प्रतिशत था और मैचिंग ग्रान्ट फ्रौम बिहार गवर्नमेंट 25 प्रतिशत था । इन्होंने बदल दिया । क्यों बदला ? हम समुन्नत हो गए क्या? अमरीका हो गए क्या कि आपने कटौती किया ? अब जनाब मोदी जी ने इसको 60 प्रतिशत किया केन्द्रांश और 40 प्रतिशत किया राज्यांश । क्यों जुल्म किया ,क्यों यह सितम ढा रहे हो ? क्या भाजपा वाले प्रेम कुमार जी की धरती नहीं है क्या ? हजरत जब राजीव गांधी विद्युतीकरण ग्रामीण योजना थी उस वक्त बिहार को मिलता था 90 केन्द्रांश और मैचिंग ग्रान्ट हमारे बिहार का था 10 तो अब कौन सी आफत आ गयी? क्या हमने गलती की तो आपने सजा दी । जब पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का आगाज हुआ हमने विरोध नहीं किया । वेल्कम किया । देश के महान लोग थे लेकिन बिहार पर जुल्म क्यों किया ? यहॉ केन्द्रांश 90 से घटाकर 60 कर दिया और मैचिंग ग्रान्ट बढ़ाकर 40 कर दिया तो क्या होगा बिहार का ? हम मरेंगे तो आप बचेंगे क्या ? जनाब अध्यक्ष जी , इस बदलाव के कारण इस बजट में 2016-17 में बिहार सरकार पर 4 हजार 5 सौ करोड़ का ज्यादा भार पड़ेगा । यह किसपर जायेगा ? गांव के गरीब ,मजलूम रिक्शे वाले ,पढ़े लिखे लोग आपपर हम पर किस पर जायेगा ? यह क्यों जुल्म किया ? यह मैं बजाप्ता अदब के दायरे में आपके सामने इस बात को रखता हूँ । मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो

मंजूरे खुदा होता है । इसको कौन टालेगा ? नीतीश जी की सरकार हर क्षेत्र में निरंतर विकास कर रही है । मैं एग्जामपल देता हूँ जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियों के नामांकण में गुणात्मक वृद्धि हुई । अब आप मान लो आप देखते हैं झुंड के झुंड टोली के रुप में यूनिफौर्म धारण करके जब लड़कियाँ साईकिल पर सवार होकर निडर होकर स्कूल जाती हैं तो लगता है कि वसंत आ गया । वह एक समां बन जाती है और उसमें से आवाज आती है धीमी सी नीतीश जिन्दाबाद की, नीतीश जिन्दाबाद की । क्यों नहीं आपने किया? आपको भी मौका मिला था । जनाब , लाखों मां बाप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की इस कारगुजारी से प्रभावित होकर बिहार के लाखों मां बाप ने हजारों दुआएं दी जिन्दा रहो नीतीश अमन से, इस देश का विकास करो । प्रदेश की रखवाली करो । महोदय, इस तरह पथ निर्माण, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विद्युत के क्षेत्र में, उद्योग, अल्पसंख्यक, पर्यटन, सिंचाई, स्वास्थ्य अनुसूचित जाति और जन जाति,नगर विकास, विज्ञान एवं प्रावैधिक आदि सब क्षेत्रें में लगातार बिना बेईमानी के विकास का क्रम तेजी से चल रहा है । महोदय, 7 निश्चय की जानकारी सबको है । लेकिन खिल्ली उड़ाया जा रहा है

सत सईया के दोहरे, अरू नाविक के तीर,
देखन में छोटन लगे, घाव करे गम्भीर ।

लाईन तो है बहुत छोटा हर घर नल का जल ,आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं । इस कायनात में , इस ब्रह्माण्ड में इस धरती पर कुदरत ने सबसे बेहतरीन चीज इंसानों को जीवों को बक्शा है वह है हवा और उसके बाद पानी । क्यों नहीं आपने उसको हर घर को नल का जल देने के बारे में सोचा ?

क्रमशः

टर्न-12/विजय: 02.03.16

श्री मो0 इलियास हुसैन: क्रमश: - यह तो नहीं कर रहे हैं कि हर घर को नल से बंद कर देंगे । आपको खूबियां गिनानी चाहिए । सिद्दकी साहब पर अटैक कर रहे हैं, आप अटैक कर रहे हैं मुख्यमंत्री पर । मैं जिक्र करना चाहूंगा शौच निर्माण, घर का सम्मान । यह छोटा सा वाक्य है । हमारे लाज के रूप में बहु बेटियां खुले में शौच करने जाती थी किसको अच्छा लगता है । कौन ऐसा शख्स है हिन्दुस्तान के सरजमीन पर, बिहार में जिसको अच्छा लगता हो । इन प्रयासों को, नीतीश जी के इन प्रयासों को पूर्णत: सहयोग देना होगा । हमारे घर की वाकई में बेटिया जब घर में यह अपना काम इस्तेमाल करेंगी तो हमारा शान बढ़ेगा । ताना कसे जाते हैं गांवों में शादियां रूक जाती हैं । तीन तल्ला मकान है उनकी बहु बेटियां बाहर जाती हैं । उस शान और इज्जत मर्यादा को जिंदा रखने के लिए नीतीश जी का यह प्रयास वैसा ही है जैसे नील आर्म स्ट्रांग ने छलांग लगा के चांद की धरती पर उतारा अपने शरीर को और इस संसार के कब्जे को । महोदय बहुत सारे सात निश्चय में है । बिहार जैसे बड़े आबादी वाले राज्य में नीतीश जी के हाथों विकास होगा, गरीबों को रोजी मिलेगी । बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा । इंसपेक्टर राज पूर्णत: समाप्त होगा । लॉ एंड आर्डर दुरूस्त होगा । इस देश के चेहरे पर लगा काला धब्बा साम्प्रदायिकता का नामोनिशान समाप्त होगा । वह शख्सियत है नीतीश कुमार जिसके ही हाथों होना है । महोदय, मैं इस शख्स के कारगुजारी हूं जिसको देश देख रहा है,प्रदेश देख रहा है, नीति आयोग सराह रहा है । क्या कहूंगा लेकिन इतना कहूंगा नीतीश जी की शख्सियत पर-

नहीं तेरा नशेमन कफ्रे सुल्तानी के गुंबद पर,
तेरी शाही है बसेरा कर हिमालय की उंचाई पर ।

ये है नीतीश कुमार । आपको काटना है तर्को से मेरी बात को काटकर देखाइये । जरा आह गरीबा कहर खुदा, इसको भी घ्यान रखना होगा आपको, सरकार को और हमको । अंत में गरीबों के हित में कुछ सुझाव मैं सरकार को देना चाहूंगा । राज्य में बी0पी0एल0 सूची के निर्माण में कुछ गड़बड़िया हुई जिसके कारण बी0पी0एल0 लोगों का नाम ए0पी0एल0 में चला गया और

ए0पी0एल0 के योग्य लोगों का नाम बी0पी0एल0 में चला गया । इसे व्यापक अभियान चलाकर सुधारा जाय । नं0-2 सरकार ने इंदिरा आवास का निर्माण काफी कराया । इस सरकार ने अधूरे इंदिरा आवासों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री शताब्दी जीर्णोद्धार योजना जब इंदिरा आवास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री शताब्दी प्रोत्साहन योजना भी शुरू किया । लेकिन फिर भी एक बड़ी आबादी झोपड़ियों में रहने के लिए विवश है । इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना है । इसलिए इंदिरा आवास के निर्माण हेतु व्यापक अभियान चलाया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक आवास विहीन गरीबों को आवास मुहैया हो सके । जो कमियों को स्वीकार करेगा मेरी आशा है, उम्मीद है वही सुधार करेगा । 3-सरकार द्वारा भूमिहीन आवास विहीन लोगों के लिए आवास भूमि क्रय नीति के तहत 3 डिसमिल जमीन खरीद कर देने का निर्णय लिया गया है फिर भी एक बड़ी आबादी भूमिहीन है । इसी के कारण उसे इंदिरा आवास की स्वीकृति नहीं होती है । जमीन क्रय की गति धीमी है क्योंकि जमीन क्रय हेतु निर्धारित दर कम है । इसको बढ़ाने की जरूरत है इसके लिए अभियान चलाने की आवश्यकता है ताकि सभी भूमिहीन गरीबों को उपलब्ध हो सके और तत्पश्चात आवास का निर्माण हो सके । फिर गरीब गायेंगे- नीतीश जी का दाना, मन लगा के खाना और तेरह दिन का रास्ता बारह दिन में जाना । जयहिंद ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री लक्ष्मेश्वर राय ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय: आदरणीय अध्यक्ष जी, बजट भाषण पर बोलने के लिए जो अवसर दिया है मैं उसके लिए आभारी हूं । बजट भाषण देखकर लगता है कि बिहार के जो खासकर गांव और दिहात में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सौहार्दता के लिए, उनकी गरीबी दूर करने के लिए, सामाजिक जो मेल है उनके लिए किया गया है। खासकर सात निश्चय पर देखने से लगता है कि देश और दुनियां में माननीय मुख्यमंत्री जी एक नया दिशा देना चाहते हैं । लगता है कि बिहार का जो इतिहास था, बिहार का जो गौरव था, जो पहला गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र राज था , दुनिया का पहला जो गणतंत्र वैशाली हमारा राज्य था । लगता है कि उसी अनुरूप में आने वाले समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को उंचाई देना चाहते हैं । खासकर सात निश्चय पर जो शिक्षा में बदलाव के लिए जो बजट बढ़ाये हैं और शिक्षा का जो परिणत रूप में जैसे शुरू में प्राथमिक और मध्य विद्यालय को मकान और भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुआ उसके बाद फिर हाईस्कूल के लिए उन्होंने मकान बनाये, फिर शिक्षकों की बहाली हुई,

आज की तिथि में फिर डिग्री कॉलेज की बात और डिग्री कॉलेज बनाने का भी प्रस्ताव रखे हैं । लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यह कहना चाहते हैं बिहार को कि आने वाले समय में जो हमारा शिक्षा का स्तर था और दुनिया के लेवल हम शिक्षा का स्तर बढ़ा दें । और जो क्षेत्र है खासकर नशाबंदी वाले में नशामुक्ति आंदोलन नशाबंदी जो रोक दिये हैं हमको लगता है कि खासकर गरीब लोग जो नशा का शिकार होते थे नशा का शिकार होकर गरीबी में धकेले जा रहे थे । आज नशा का बंदी करा के शराबबंदी करा के लगता है कि आने वाले समय में गरीबों की शिक्षा गरीबों को दें उससे आय है वह बढ़ेगा और शिक्षा में भी बढ़ेगा ।खासकर सात निश्चय पर हम आभार प्रकट करते हैं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी और उसको मजबूत करें और एक दिशा दें ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति,श्री रामनारायण मंडल ने आसन ग्रहण किया)

श्री लक्ष्मेश्वर रायः सभापति जी, खासकर के हम एक नये सदस्य के रूप में हैं इसलिए सामाजिक न्याय पर हम बोलना चाहते हैं । सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामाजिक न्याय धारा के तहत हमारे जैसे लोगों को हमारी परिस्थिति में भी बढ़ाना चाहते हैं । हम चाहते हैं खासकर विपक्ष से जो उनकी भूमिका है हमलोगों को सीखने का भी मौका दें । इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार का गौरव दुनिया में बढ़े । लेकिन प्रतिपक्ष की जो भूमिका है हमको लगता है कि केवल हिंसा मुद्दा बनाना या फिर हंगामा करना लगता है । हमारे नये जैसे सदस्य को सीखने का मौका नहीं मिलता है । हम भी सोच रहे हैं कि अखबार में फोटो खींचा लें, अखबार में मिडिया का मिडिया में एक अखबार कॉलम है और हम अपना मेसेज जनता तक दें । हम आदरणीय विपक्ष के नेता से कहेंगे कि हंगामा रोका जाय । हंगामा वाली जो आपकी रणनीति है उसको आप रोकिये । इसीलिये कि आप अति पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं । लेकिन जब गरीब की बात होती है तो आपके लोग हंगामा करते हैं । हमको लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो गरीब की बात करते हों गरीब का मुद्दा आता है उसमें पक्ष के साथ आप नहीं रहते । निश्चित रूप से सकारात्मक भूमिका विपक्ष का रहना चाहिए । ताकि आम लोगों को और ढेर लोगों को भी सीखने का मौका मिले । कल ठीक है कि माननीय सदस्य जी ने आपको बड़ी गंभीरता से बोले कि इस पर सोचना चाहिए । हम भी आग्रह करते हैं कि खासकर विपक्ष के नेता और विपक्षी दल से कि हमलोगों को मौका दें सीखने

का । केवल फोटो का मुद्दा बनाकर नहीं दिशा देना चाहिए । बिहार का जो दिशा और प्रतिष्ठा बढ़ रहा है दुनिया में उस में आपकी भी भूमिका सराहनीय हो । आपकी भावना, आपका जो पहल हो वह विकास आधारित हो । बिहार को विकसत राज्य बनाने की भूमिका हो । इन्हीं चंद बातो साथ हम आभार प्रकट करते हैं सभापति जी को कि आपने हमको बोलने का समय दिया ।

टर्न-13/बिपिन/2-3-16

डा0 जावेद : बहुत-बहुत शुक्रिया । सभापति महोदय, आज मैं हमारे फाइनांस मिनिस्टर और माननीय मुख्यमंत्री दोनों को शुक्रिया अदा करने के लिए और इस बजट के फेवर में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

विपक्ष के बड़े सिनियर नेता ने कहा कि पिछले सालों में कांग्रेस के राज्य में और उसके बाद राज्यों में बिहार की जो हालात है वह बेहतर नहीं, बदतर हुई है लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार में जब कांग्रेस की राज्य थी तो बिहार सबसे अच्छा राज्य माना जाता था और पिछले दो सालों से जब से कांग्रेस का समर्थन है, जब से कांग्रेस का इस महागठबंधन में योगदान है तो उसी का नजरिया है सर कि आज जो बजट पेश हुआ है जिसमें अगर हम गौर से देखें तो हर सेक्शन के लोगों का ध्यान रखा गया है । गरीब-से-गरीब, पिछड़ा-से-पिछड़ा सबको इसमें सम्मिलित किया गया है और गौर करेंगे 29तारीख को सेंट्रल बजट पर तो पिछले दो सालों की तरह इस साल भी उन्होंने सिर्फ एक सेक्शन पर जोर दिया है और वह है जो ऑलरेडी खुशहाल है । मैं मुख्यमंत्री महोदय को और फाइनान्स मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे युवाओं के लिए एक हजार रूपया दो साल के लिए, हमारे युवा जो 12क्लास पास करते हैं उनके पढ़ाई के लिए चार लाख रूपए सॉफ्ट लोन के जरिए, इसके अलावा महिलाओं को इनकरेज करने के लिए उन्होंने जो 35परसेंट रिजर्वेशन रखा है उसको हमलोग वेलकम करते हैं । घर-घर में बिजली पहुँचाने की जो बात कही गई है मुझे उम्मीद है यह जल्द-से-जल्द होगा । उसी तरह, घर-घर में नल पहुँचाने से बेहतरीन बात हो ही नहीं सकती, लेकिन मेरा सुझाव होगा कि जब तक यह नहीं हो पाता है तब तक जो पुराना स्कीम हर पंचायत में पांच हैंडपम्प और टाउन में दो

हैंडपम्प देने की बात है उसको जारी रखने से मेरे खयाल से लोगों को काफी आसानी होगी ।

साथ ही, घर-घर पक्की सड़क, शौचालय निर्माण करना और स्कूल, पारा मेडिकल कॉलेज, टेक्निकल कॉलेजेज इलाके में खोलने का हम खैरमक्दम करते हैं । मैं किसनगंज जिला से आता हूं । अगर किसनगंज जिले की आप बात करें, सीमांकन की बात करें तो साक्षरता में परकैपिटा इनकम में इन्फ्रास्ट्रक्चर में चाहे वह रोड के माध्यम से हो, पुल के माध्यम से हो या एजुकेशनल इंस्टिच्युशंस के तुलना में हो, हमलोग पीछे रह रहे हैं । कुछ सालों में सरकार का ध्यान उधर रहा है । मेरी गुजारिश होगी कि जिस तरह पांच मेडिकल कॉलेज बिहार सरकार ने खोलने का निर्णय किया है, एक किशनगंज में भी खुलना चाहिए । यह पांच मेडिकल कॉलेज बिहार के लिए नाकाफी है, मेरी गुजारिश होगी कि इन पांच मेडिकल कॉलेजों को अगले पांच सालों में कम-से-कम दस करें । उसी तरह, जैसा मैंने कहा, रोड की किल्लत है, हमारे यहां ब्रिजेज की किल्लत है । हमारे यहां एक सड़क, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं तो रोड का विभाग देखते हैं मोटा थाना आजाद नगर से लेकर भुजरा घाट तक एक रोड जिसका टेंडर भी निकल गया था पेपर में, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है शुरू वहां पर तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उसको भी जल्द-से-जल्द चालु किया जाए । नन्हापुरी का एक रास्ता है जहां से दसो हजार के लोग आते-जाते हैं वहां भी किल्लत है । उसी तरह, बेबी चॉक से सोनापुर और चिचुआ बरही से इसलामपुर एन.एच. 16 से कनेक्ट करता है, मेरी गुजारिश होगी कि इस फाइनान्शियल इयर में इसको टेकअप करें । उसी तरह, पुल-पुलिया के बारे में मुझे कहना है कि महानन्दा में भूटा थाना में और डॉक नदी पर खरखरी से उसको काम करवाने की जरूरत है । किशनगंज के बीच में सर, रमजान नदी बहती है । पिछले कुछ महीनों में और कुछ सालों में देखा गया है कि उसके दोनों तट पर जमीन कब्जा करके लोग घर बना रहे हैं जिसके वजह से नदी आज नाला का रूप ले रही है । मेरा आग्रह होगा कि इस पर भी सरकार गौर करे और इससे अतिक्रमण हटा कर इसको बेहतर एक शहर बना सके । सर, एजुकेशन में, और जैसा कि कल-परसों जब बजट पेश हुआ तो फाइनांस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारा परकैपिटा इनकम आज भी बहुत पीछे है कई राज्यों में और अगर हमें नेशनल लेवेल पर पहुँचना है तो उसके लिए कम-से-कम बीस साल लगेंगे । मैं मानता हूं सर कि जिस तरह की योजनाओं को उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की मंशा रखी है इसमें अगर हमारे ऑपोजिशन के साथियों का सहयोग रहा और हमारे जो ऑफिसरान हैं उनकी रेस्पौंसिबिलिटी फिक्स हुई तो मुझे यकीन है यह हम अगले पांच सालों में

इसको एचीव कर सकेंगे । मेरा सुझाव होगा कि जिस तरह एजुकेशन के वगैर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं । अगर बिहार की पहचान है तो वह है एजुकेशन से । अगर हमारी पहचान है वह नालन्दा से है बोधगया से है । इसका हमलोगों को भरपूर फायदा उठाना चाहिए । आज पूरे बजेटरी एलौकेशन का लगभग 25परसेंट एजुकेशन में जाता है। लेकिन आज भी हमारे बच्चे तालिम के लिए चाहे स्कूल हो , कॉलेजेज हो,दसो हजार करोड़ रूपया सालाना बाहर जाकर खर्च करते हैं । हमारे यहां हमारे बिहार के लोग सबसे ज्यादा परसेंटेज में आई.ए.एस., आई.पी.एस. बनते हैं । हमारे बिहार में अगर दुनिया भर में मशहूर है तो सुपर-30 जैसे जो संस्थान हैं, वह मशहूर है । लेकिन हमारे बच्चे हजारों, दसो हजार के तादाद में कोटा जाकर ट्रेनिंग लेते हैं । मेरी गुजारिश होगी कि इसमें जो इसको खाली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं देखा जाए, इस डिपार्टमेंट को प्राइवेट लोगों को भी इनकरेज किया जाए । हमारे बिहार के लोगों को, जिला के लोगों को ब्लॉक्स के लोगों को । इसके लिए मेरा सुझाव होगा कि जिस तरह जमीन, हमलोग सरकारी जमीन का उसको कम रेट से स्कूल के लिए दें, उसको कॉमर्शियल टैक्स न लगाएं, बिजली को कॉमर्शियल बिजली न लगाएं और अगर लोन लेना हो तो उसको सबसिडी दें ताकि हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर न जाना पड़े । हमारे बच्चों को अच्छी तालिम यहां मिले । चीप चिफमिनिस्टर ने अंग्रेजी और हिन्दी बोलनेके भी जोर दिया है ताकि हमारे बच्चों को अच्छा इम्प्लायमेंट मिल सके । उनका प्रमोशन अच्छा हो सके । तो उसी के तहत मैं चाहूंगा कि इस वेन्यू को न सोचें । इसको न गवॉएं । मैं एक एक्जाम्पुल देना चाहता हूं । वर्ष 2000 में जब मैं स्टेट मिनिस्टर था लेबर इम्प्लायमेंट का तो तामिलनाडु जाने का मौका मिला था मुझे । वहां पर छह करोड़ की आबादी थी और उस छह करोड़ आबादी पर 600 आई. टी.आई. थे । और हमारी आबादी 10करोड़ के आसपास थी,चूकि झारखंड-बिहार एक साथ था, और हमारे यहां सिर्फ 37आई.टी.आई. थी और चार-पांच-दस ज्यादे से ज्यादे प्राइवेट इंस्टिच्युट्स थे । क्यों न हम उसका एक्जाम्पुल लेते हुए यहां पर उसको इम्प्लीमेंट कराएं । क्यों हम अपने बच्चों को अपने युवा साथियों को क्यों न हम यहां पर ट्रेनिंग दें जिससे हमारा इम्प्लायमेंट भी होगा, जिससे हमारा परकैपिटा इनकम भी बढेगा, जिससे हमारी हालात भी बेहतर होगी ।

सर, एजुकेशन में चूंकि इसमें मदरसा और संस्कृत टीचर्स भी आते हैं, पहले भी कइ मरतवा हमने , जब-जब मौका मिला , हमने कहा हमारी गूजारिश होगी, चूंकि यह भी तालिम इम्पार्ट करते हैं तो इनकी तनख्वाह और सइनकी

फैसिलीटीज भी सरकारी टीचर्स की तरह जैसा होता है उनकी तरह इनको भी मिलनी चाहिए ... क्रमशः

टर्नः-14/राजेश/2.3.16

श्री मो0 जावेद, क्रमशः- मेरी गुजारिश होगी कि मदरसों में भी बिल्डिंग, फर्नीचर एवं बाउन्ड्री का प्रोविजन होना चाहिए । इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट में 500 करोड़ का बजट रखा है, मैं इसपर सुझाव देना चाहता हूँ कि सरकार हमारे युवाओं को अलग-अलग जिलो में, प्रखंडों में जानकारी दें और छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज करें और उस छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज से हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्लायमेंट दे सकेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का मनुफैक्चरिंग कर सकेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की आबादी और हमारा जो आबादी है,उसका फायदा उठाना चाहिए, दूसरे राज्य के लोग हमारी आबादी का फायदा उठाते हैं, हम चाहेंगे सर कि सरकार इसपर गौर करें और जब हमारा रेडिमेड मार्केट सवा 10 करोड़ का है, तो उसका हमलोगों को भरपूर फायदा उठाना चाहिए,यह मेरा मानना है । ए0एम0यू0 के संबंध में जो सेन्टर से हमें मिला है लेकिन सेन्टर से जो राशि हमें मिलनी चाहिए उसमें बहुत कोताही हो रही है, मैं चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी अपना नजरिया कन्स्ट्रक्टिव रखें । सर, एस0सी0/एस0टी0 में 700 करोड़ का एलौकेशन है, मेरी गुजारिश होगी कि उनकी हालात देखते हुए कम से कम एक हजार किया जाय । अब मॉयनरिटी जिसकी आबादी लगभग उतनी ही है, उसको 300 करोड़ से भी कम रखा गया है,मेरी गुजारिश होगी कि उसको भी एक हजार करोड़ एलौकेट करने की कोशिश करें । उसके साथ-साथ मेरी गुजारिश होगी कि मॉयनरिटी डिपार्टमेंट में इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है,जो वक्फ बोर्ड की जमीन है,यह लाखों एकड में है,मेरी गुजारिश होगी कि सरकार जिसतरह से कब्रिस्तान की घेराबंदी कर रही है,उसीतरह वक्फ बोर्ड की जमीन को उसको आईडेंटिफाई करके, उसको इनक्रोचमेंट से हटाकर उसको पोजेशन में लेकर उसकी बाउन्ड्री करें......... (व्यवधान)

सभापति (श्री राम नारायण मंडल):- अब आप समाप्त करें ।

श्री मो0 जावेद:- सर, दो मिनट में अपनी बात को खत्म करुंगा । इसको छोटे-छोटे पिरियड में लीज दे करके रेवेन्यू जेनरेट करें, जिससे मॉयनरिटी की हालत बेहतर हो सके, एग्रीकल्चर में सर क्वालिटी सीड्स टाईम पर नहीं मिलती, इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि यह टाईम से मिलना चाहिए । धान जो खरीदा जाता है, कम से कम वह दो महीना कबल होना चाहिए, जिसतरह से धान का मिनिमम प्रॉयस दिया गया है, मेरी गुजारिश होगी कि चाय की पत्ती की खेती पर जिसपर हमलोग नाज करते हैं कि बिहार में भी चाय की खेती होती है,उसमें भी मिनिमम परचेज प्राईस का घ्यान में रखना चाहिए । सर, पिछले कुछ महीनों से जब भी अखवारों में देखते हैं हमलोग तो कुछ हमारे साथियों का बयान आता है कि बिहार जंगल राज हो रहा है, मेरी गुजारिश है, ऑकड़े हैं हिन्दुस्तान के अलग-अलग राज्यों के, उसमें हमारा क्राइम रेट पोपुलेशन के आधार पर अगर देखा जाय, तो 22 वॉ है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उस दिन बताया था, तो हमलोग ऐसा कहके अपने बिहार के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, मेरी गुजारिश होगी सर कि आज के माहौल में, हमारा बिहार लॉ एण्ड ऑर्डर के मामले में बहुत बेहतर है बाकी राज्यों से और खास करके दिल्ली में जो हालात है, मुझे तो ऐसा वहॉ पर खौफ होता है कि कहीं किसी चार्ज में किसी को अंदर न कर दिया जाय, तो इसीलिए मेरी गुजारिश होगी कि इसपर भी घ्यान दिया जाय और आखिर में आपने हमें जो बोलने का मौका दिया, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं । थैंक्यू सो मच ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल):- माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी । आपके पास दो मिनट का समय है ।

श्री राजू तिवारी:- बहुत-बहुत धन्यवाद । सभापति महोदय, नया सदस्य हूं, इससे पहले भी एक दो बार मौका मिलते-मिलते रह गया, अगर बोलने में कोई त्रुटि हो, तो क्षमा करेंगे । मैं सरकार का घ्यान दो तीन तरफ जो मुझे समझ में आता है उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । जैसा कि अभी हमारे सिनियर एम0एल0ए0 साहब कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, सरकार उसपर सिरियस है, अभी मै अपने विधान सभा क्षेत्र गया था दाह संस्कार में, एक गरीब आदमी था, उसके दाह संस्कार में हमने देखा कि गाड़ी से निकाला हुआ टायर रखा गया था, बडा ही दुख होता है लकड़ी के अभाव में, लकड़ी अभी गॉव में उपलब्ध नहीं हो रहा है, बरसात के दिनों में

तो और स्थिति भयावह है, लकड़ी के अभाव में चूंकि हरा पेड़ लगातार कट रहा है और इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ रहा है और सरकार से आग्रह करुंगा आपके माध्यम से, बिहार सरकार के डिप्टी सी0एम0 बैठे है, वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं, हर जगह बिजली तो पहुंच गयी है, लगभग सारे प्रखंडों में बिजली पहुंच गयी है लेकिन आग्रह करुंगा कि प्रखंड स्तर पर गॉव में विद्युत शवदाह गृह का तार जोड़ दें चूंकि लकड़ी का गॉव में जो जबरदस्त किल्लत है, दूसरी तरफ बड़े-बड़े बिल्डिंग बन गये हैं, मैं अभी अपने क्षेत्र में उत्क्रमित हाइ स्कूल जो बना है, बहुत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग बन गया है सर लेकिन बड़े ही यह दुर्भाग्य की बात है,अभी हमलोग वाहवाही कर रहे हैं कि सुशासन की सरकार है लेकिन कहीं भी शिक्षक नही हैं, 10वीं में एडमिशन ले लिये हैं बच्ची बच्चियॉ लेकिन एक भी शिक्षक नहीं हैं, बिल्डिंग तो बन गयी है लेकिन शि।क्षक के अभाव में वहॉ पढ़ाई नहीं हो रही है,इसपर भी सरकार को घ्यान देना चाहिए, आज आजादी का इतना साल हो गया सर लेकिन मैं बड़ा ही दुर्भाग्य के साथ यह कहना चाहता हूँ कि आज भी बिहार के गॉवों में गरीब लोग इलाज के अभाव में मर जाते है, बड़े लोगों का तो इलाज हो जाता है लेकिन गॉव में जो गरीब हैं, उनका इलाज नहीं होता है और वे मर जाते हैं गॉव में, यह स्थिति है, इसलिए सरकार से अनुरोध करुंगा, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का सात निश्चय है, मैं चाहूंगा, सरकार से आग्रह करुंगा आपके माध्यम से, कि उसमें यह भी निश्चय में रखा जाय कि कोई भी गरीब का बच्चा कोई भी गरीब महिला बिना इलाज के न मरें, अगर अब बिना इलाज के कोई गरीब मरेंगे तो बड़ी ही शर्मिन्दगी । इन्हीं शब्दों के साथ आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल):- माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव ।

श्री ललित कुमार यादव:- सभापति महोदय, आज 2016-17 का बजट पेश हुआ है सरकार की तरफ से, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । हम अपने वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते है कि इन्होंने जो बजट पेश किया है 2016-17 का, इसमें सबसे विशेषता कई माने में सभापति महोदय है । गठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहली बजट है । गठबंधन की सरकार भारी जनादेश के बाद बना । हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कॉग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गॉधी जी, सारे नेता और पार्टी के गठबंधन के बाद, जो बिहार में

जनादेश मिला महोदय और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह बजट पेश किया है, यह स्पष्ट रुप से परिलक्षित होता है कि गॉव के गरीब, किसान और अभिवंचित वर्ग का ख्याल रखकर यह बजट तैयार किया गया है और इस बजट में और भी कई मामलों में विशेषता है । आज हमारे राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी, जिसमें राजस्व संग्रह में कमी आयेगी, हमारा केन्द्रीय जो राज्यांश था, उसमें भी भारी कटौती हो रही है, उसके बावजूद भी बिहार की तरक्की के लिए जो बजट पेश हुआ है महोदय, वह काफी प्रशंसनीय योग्य है।

क्रमशः

श्री ललित कुमार यादव (क्रमशः) हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी की सोच है सामाजिक न्याय, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की सोच है न्याय के साथ विकास । सारे बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये गांव, गरीब और बेरोजगारों का विकास कैसे हा ?, जो हमको जनादेश मिला है, उस जनादेश का कैसे सम्मान हो, उसमें इनका 7 निश्चय कार्यक्रम भी है । हमारे माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव जी कल सुशासन के कार्यक्रम, सुशासन के कार्यक्रम बोल रहे थे । सभापति जी, हमलोग उस पर आयेंगे । मा0नेता,प्रतिपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे थे । नन्द किशोर यादव जी बोल रहे थे कि हम 20 साल से 21 साल से इस सदन के सदस्य हैं । सभापति महोदय, हमलोगों का भी इस सदन में 20, 21 साल हो गया । हम इनको सत्ता में भी देखे हैं जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और इनलोगों के पास कैसे मलाईदार विभाग था और सभी मलाईदार विभाग के मंत्री थे और नीतीश कुमार केवलम् कर रहे थे । बिहार का विकास, नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय कार्यक्रम है, बिहार में शराबबंदी लागू करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, राजस्व संग्रह जहां से भी करना हो, बिहार का विकास करना है, नीतीश कुमार का संकल्प है, हमारे गठबंधन का संकल्प है जहां से भी राशि की मुहैय्या करना पड़े, राज्य के जो संसाधन बढ़ाने पड़े लेकिन हम बिहार का विकास करते रहेंगे, जो हमलोगों को भारी जनादेश पिछले विधान सभा चुनाव में मिला है, मैनडेट का हम सम्मान करेंगे और हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं इस बजट के लिये, वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देते हैं, इस चुनाव में जो मैनडेट मिला, मैनडेट का इन्होंने सम्मान किया है । महादलित समाज के लोग, दलित समाज के लोग जो पैसा कमाते थे दिनभर, शाम में वे सारे पैसे गवां देते थे, चूल्हा नहीं जलता था मुशहर समाज के घरों में । हमारे मांझी साहब नहीं हैं । खास करके मुशहर समाज में । महोदय, नीतीश कुमार जी ने जो यह कार्यक्रम लाया है, वह काबिले-तारीफ हैं । हमलोग गांव-घर से आते हैं, हमलोग उसी समाज से आते है, हमलोगों के क्षेत्र में महादलित समाज के लोग हैं, दलित समााज के लोग हैं, उनके घरों में क्या परेशानी थी, शाम में उनके घरों में चूल्हा नहीं जलता था, सारे पैसे उनके खर्च हो जाते थे शराब में । मुख्यमंत्री जी ने राजस्व का परवाह नहीं किया, राज्य का विकास कैसे होगा, राज्य के विकास के लिये संसाधन कैसे अर्जित करने होंगे, सात निश्चय कार्यक्रम जो नीतीश जी का है, युवाओं का बल, हमारे बेरोजगार युवा, जिनको रोजगार नहीं मिलता था, वेरोजगार के अभाव में भटकते रहते थे, उनके माता-पिता के ऊपर जो खर्च था, रेलगाड़ी से या बस से जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हम 1 हजार रूपया भत्ता के रूप में 20 से 25 साल के

बेरोजगार नवयुवकों को देंगे और दो सालों तक देते रहेंगे, जबतक उनको नौकरी नहीं मिल जाती है, उनको सहूलियत होगी ।

व्यवधाान

तिवारी जी, आप पहली बार आये हैं । आप सुनिये ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : आप आसन की ओर देख कर बोलिये ।

श्री ललित कुमार यादव : सभापति जी, आसन की ओर देख कर ही हम बोल रहे हैं, मेरा अगल-बगल ध्यान नहीं जा रहा है । कल नन्द किशोर जी बोल रहे थे सुशासन के कार्यक्रम कल प्रेम कुमार जी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहे थे, हमलोग भी सुन रहे थे, कुछ बातें कहेंगे तो हो सकता है, ये लोग सदन से बाहर न चले जायें । हमलोग नीतीश कुमार जी के सरकार में नहीं थे । सभापति जी, बीजेपी के साथी थे । आप भी थे । आपके प्रेम कुमार जी जो अभी प्रतिपक्ष के नेता हैं, नन्द किशोर यादव जी कल बोल रहे थे सुशासन के कार्यक्रम । भाई, 9 साल तो आप सुशासन के कार्यक्रम में हां में हां मिला रहे थे । आप नीतीश कुमार केवलम् कर रहे थे ं। आप कभी 60 हजार, 70 हजार से जीते थे, इस बार बड़ी मुश्किल से दो-ढाई हजार वोट से जीते हैं । नन्द किशोर बाबू नीतीश कुमार कवेलम् नहीं किये इसीलिए । आप नीतीश कुमार कवेलम् नहीं किये इसीलिए दो-ढाई हजार से जीते । प्रेम कुमार जी बोल रहे थे कि रंगदारी हो रहा है, ये लूट हो रहा है, ये हत्यायें हो रही है, ये अपहरण हो रहा है । प्रेम कुमार जी आप भी मलाईदार विभाग नगर विकास मंत्री, पथ निर्माण मंत्री हुआ करते थे 2005 और 2010 में । हमलोग साक्षी है, हमलोग इसी सदन के सदस्य थे । हमलोग भी विपक्ष में थे । आपने क्या सुशासन का कार्यक्रम किया । आप कल बोल रहे थे, आप राज्यपाल के अभिभाषण पर रंगदारी, लूट, हत्या, बलात्कार । आप जब सुशासन के कार्यक्रम में हां में हां मिला रहे थे । नीतीश कुमार जी ने जबतक आपको ठोकर मार करके हटाया नहीं, तब तक आप हटे नहीं । क्योंकि आप कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे । आपको हटाया गया । धक्का देकर हटाया गया ।

सभापति (श्री राम नारायण मंडल) : एक मिनट ।

श्री प्रेम कुमार: सभापति महोदय, जब नीतीश कुमार जी के साथ भाजपा थी तो राज्य में शांति थी, कानून का राज था । जब से आर0ज0डी0 के साथ ये लोग हो गये, तब से हत्या अपराध बिहार में बढ़ा है ।

श्री ललित कुमार यादव : सभापति जी, ये लोग जंगल राज, जंगल राज करते-करते, 9 सालों से हमलोग सुन रहे थे । जब नीतीश कुमार केवलम् कर रहे थे इसीलिए आप जीत करके सरकार में आये

थे और आज आप कहां पहुंच गये ? जंगल राज ने आपको कहां पहुंचा दिया ? जंगल राज के मुखिया आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी हुआ करती थी जिनका नाम आप भ्रमित करना चाहते हैं, सुन लीजिये । 10 साल नहीं, 15 साल शासन किये, 15 साल जंगल राज करके शासन किये । भाजपा के लोग, नन्द किशोर जी का वही भाषा, बजट भाषण पर बोले रहे थे, आप राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे थे । आप की भी वही भाषा । लगता है कि भाजपा के लोग बिहार का विकास ही नहीं चाहता है ।

व्यवधान

हमारे नेता श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी साहब, जब वित्त मंत्री थे, कहा करते थे कि नीतीश कुमार जी आप होशियार रहिये, आपके बगल में मोदी जी जो बैठे हुये हैं, उस जगह पर कभी कैलाशपति मिश्र जी बैठा करते थे और जहां आप बैठे हैं वहां हमारे जननायक कर्पूरी जी बैठा करते थे। जिस तरह इन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को ठगने का काम किया, उनको हटाने का काम किया, आपके साथ भी धोखा और छल करेंगे । सिद्दिकी जी का स्टेटमेंट है । उस समय वित्त मंत्री कैलाशपति मिश्र जी थे ।

सभापति : बैठे-बैठे मत बोलिये ।

श्री ललित कुमार यादव : कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं । कितना नाटक हुआ कर्पूरी जयंती के लिये । कृष्ण मेमोरियल हॉल चाहिये । भाई नियम कानून है, पहले से जब यह किसी पार्टी के लिये बुक है तो आपको कैसे आवंटित होगा ? किसलिये तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने के लिये । जिस जननायक कर्पूरी जी को सत्ता से कैसे बेदखल किये । बिहार की जनता इसे जानती है । सभापति जी, इतना ही नहीं, प्रेम कुमार जी प्रतिपक्ष के नेता हैं । नरेन्द्र मोदी,प्रधानमंत्री जी बिहार में आये थे, हाथ ऊठा-ऊठा कर बोल रहे थे, बोली लगा रहे थे बिहार की जनता की कि आप हमको बिहार विधान सभा चुनाव जीताओं, बीजेपी का सरकार बनाओं, हम 80 करोड़ देंगे, 125 हजार करोड़ रूपया देंगे । आपका यह क्या हुआ ?

व्यवधाान

श्री प्रेम कुमार : महोदय, दीघा का पुल जो है, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने शुरू किया है ।

व्यवधान

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव: सत्ता में बने रहे और मलाई खाते रहे तो उस समय नीतीश कुमार अच्छा लगे लेकिन आज नीतीश कुमार के हर कार्यक्रम उनको अच्छे नहीं लगते हैं। सभापति महोदय,पी0एम0जी0एस0वाई केन्द्र सरकार की योजना है। ये क्या किये। प्रेम कुमार जी प्रतिपक्ष के नेता हैं,क्यों न दिल्ली जाते हैं और अपने नेता प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं बोलते हैं? आज हमारा 4 हजार कि0मी0 सड़क अधूरा पड़ा हुआ है। हम लोग किसी मद से उस रोड को नहीं बना सकते हैं। इनका केन्द्र प्रायोजित योजना का राशि नहीं आ रहा है। इन्दिरा आवास का वही हाल है। जितना भी केन्द्र प्रायोजित योजना है यानी केन्द्र की दोरंगी नीति, दोहरा इनका आचरण है। कथनी कुछ और करनी कुछ, इसमें इनका भारी अन्तर है। जो वोलते हैं वो करते नहीं है और....

श्री प्रेम कुमार: महोदय,प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बिहार में 12 तारीख को दीघा पुल के उद्घाटन करने के लिए ...

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव: प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हर बात में भारत का प्रधानमंत्री बोलना सभापति महोदय कोई जरूरी नहीं है यानी प्रधानमंत्री बोल दिये तो वे पूरे भारत के ही प्रधानमंत्री होते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री थोड़े ही होते हैं। सभापति महोदय,इनकी चिन्ता है 2019 लोकसभा चुनाव। विधान-सभा के चुनाव में तो 58-52 पर आये हैं और 5-7 पर लोकसभा में आ जाईयेगा।(व्यवधान)सभापति महोदय,आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सुदामा प्रसाद: सभापति महोदय,आपने बजट पर मुझे विचार रखने का मौका दिया इसके लिए हृदय से आपका आभारी हूँ। सरकार द्वारा पेश 2016-17 के बजट में आंकड़ों की बाजीगिरी दिखलाई पड़ रही है। पिछले 10 वर्षों में 10 प्रतिशत बिहार का विकास दर बतलाया जा रहा है लेकिन बिहार में हम देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में एक भी कल कारखाना नहीं खुला है। जितने कल कारखाने पुराने हैं वो लगभग बंद है। अगर उद्योग के नाम पर कुछ खुला भी है तो वह है शराब की फैक्ट्रियां एसवेस्टस की फैक्ट्रियां खुली। पटना के नौबतपुर में कृषि योग्य जमीन का अधिग्रहण कर के और कनपा में भूदान की जमीन पर अबैध शराब की फैक्ट्री खोली गयी। आनन फानन में बिहिंया में एसबेस्टस का कारखाना खोला गया तो दरअसल विकास का जो सरकार का मॉडल है वो रोजगारविहीन है। महोदय सरकार दूसरे रोड मैप की बात कर रही है लेकिन बिहार के विकास का जो मंत्र है भूमि सुधार, इस मामले में सरकार

बिल्कुल ही चुप है। इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है कि जमीन के सवाल पर सरकार क्या करेगी। यहां के किसान त्राहिमाम् कर रहे हैं। अगर कृषि के क्षेत्र में इतना ही विकास हो रहा है तो किसानों का धान क्यों नहीं खरीदा जा रहा है। पिछले साल का बकाया पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। 29 जनवरी,2015 से 6 बटाईदार किसानों का धान तरारी प्रखंड के प्रतिनिधि भवन में पड़ा हुआ है लेकिन उनको आज तक पैसा नहीं मिला। एक किसान का ब्रेन हेम्ब्रेज हो गया इसलिए कि पैसा अब नहीं मिलेगा। यह स्थिति है किसानों की। किसान त्राहिमाम् कर रहे हैं और किसान की खेती लगातार घाटे में जा रही है। महोदय, बिहार में भी आत्महत्या की प्रवृति कहा जाय तो बढ़ रही है। किसानों के अन्दर ये बिल्कुल ही चिन्तनीय है। पिछले 22 फरवरी को बरहीं के दियारा में अपने फसल की रखवाली कर रहे एक बटाईदार किसान जनार्दन महतो की हत्या कर दी गयी गोली मार कर के लेकिन अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गये हैं। बटाईदार किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बिहार की खेती का भार उठानेवाले बटाईदार किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अगर उन्हें लाभ नहीं दिया गया तो बिहार की खेती हतोत्साहित होगी। सिंचाई की बात कही जा रही है कि सिंचाई के क्षेत्र में बिस्तार हो रहा है लेकिन हमलोग देख रहे हैं कि जितनी पुरानी नहर व्यवस्था है सब की सब जर्जर है। नलकूप बनाये जा रहे हैं लेकिन हमलोग देख रहे हैं भोजपुर जिला में 514 नलकूप में से मात्र है 144 ही चालू है। ये सिंचाई की गड़बड़ व्यवस्था है। जमीन के मामले में हमलोग यही देख रहे हैं।

सभापति(श्री राम नारायण मंडल): माननीय सदस्य अब बैठ जायें।

श्री सुदामा प्रसाद: ये तो कोई बात नहीं है। हमलोग कम संख्या में हैं तो समय नहीं मिलेगा?

सभापति(श्री राम नारायण मंडल): समय निर्धारित है। जो 3 मिनट निर्धारित समय था वही मैंने दिया है।

श्री सुदामा प्रसाद: दो मिनट में अपनी बात खत्म कर देंगे।

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) एक मिनट में बोलिये।

श्री सुदामा प्रसाद: ये श्रीबिधि की बात की जा रही है कि श्रीबिधि से सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है खेती के लिए लेकिन हमलोगों ने जो देखा, पिछले साल हाजीपुर के बैशाली जिला के सोलहों प्रखंड में खुब फसलें लहलहायी धान की लेकिन धान की वाली में दाना नहीं आया। वहां के सोलह प्रखंड के कृषि पदाधिकारियों ने और वहां के जिला कृषि पदाधिकारी ने सरकार को पत्र लिखा लेकिन आजतक किसानों को काई मुआवजा नहीं मिला, न ही नकली बीज बनाने वाली कम्पनियों पर

कोई कार्रवाई हुई। ये हमलोग देख रहे हैं खेती का हाल कि किसान किस तरह से जर्जर हो रहे हैं। मात्र जो है 835 करोड़ 41 लाख रू0 भूमि राजस्व विभाग के लिए रखा गया है और सरकार कह रही है कि 2 लाख 38 हजार परिवारों के बीच 7170 एकड़ 40

टर्न-16/सत्येन्द्र/2-3-16 ...

डी0 हमने जमीन बांटा। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। 21 लाख 85 हजार एकड़ जमीन है इतनी जमीन रहते हुए बिहार में बिहार के 70 प्रतिशत ग्रामीण शहरी और गरीब लोग आसामन के नीचे रहते हैं उनको छत नहीं है सिर पर। महोदय, हमारा यह कहना है कि इस मामले में बजट बनाया जाय और वर्षों वर्षों से जो भूमिहीन बसे हुए हैं जिस जमीन पर उसका पर्चा उनको नहीं है उनको उजाड़ा जा रहा है। जहां पर्चा की जमीन पर भी बसे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। करीब 100 गांव का लिस्ट हमने भूमि सुधार विभाग को दिया है।

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) माननीय सदस्य अब बैठ जायें।

श्री राजकिशोर सिंह: सभापति महोदय,मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूॅ। सभापति महोदय, मैं आज पहली बार बोलने जा रहा हूॅ सदन में, हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाय इसके लिए आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूॅ। इस बजट पर, मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूॅ और बजट से पहले थोड़ा पीछे जाना चाहता हूॅ। बजट आया कैसे? विगत चुनाव में हमारे नेता महागठबंधन के नेता जो वादा जनता से किये उसी के अनुरूप हमारा बजट है। हमारे वित्त मंत्री जी उस बजट को लायें हैं उसके पीछे भी जाना चाहता हूॅ। इसे बिहार की जनता देख रही है। 2014 में वादा किया गया उसका क्या हुआ? 2015 में जो वादा किया गया उसका क्या हश्र हुआ इसका तुलनात्मक विश्लेषण जनता कर रही है आज। बिहार की जनता और देश की जनता के समक्ष 2015 में जो वादा किया गया कि 15 से 20 लाख रू0 एक-एक खाता में जायेगा लेकिन कुछ नहीं हुआ।(क्रमशः)

श्री राज किशोर सिंह : ..क्रमशः... कहा गया बेरोजगार को नौकरी दिया जायेगा, कुछ नहीं हुआ । मैं आपको एक वाकया बताया चाहता हूँ सदन के माध्यम से, गाँव में एक लड़का शादी 2014 में नहीं किया कि फोकट का 15-20 लाख रूपया आ जायेगा, अगले साल शादी करेंगे, बड़े लोगों की तरह हम भी हनीमून मनाने जायेंगे । 2014 में उसकी शादी तो नहीं हुई लेकिन 2015 में वह लड़का शादी किया, उसका सपना टूट गया । 2015 में जो वायदे किये गये माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, महागठबंधन के नेता की तरफ से, हमारे नेता थे माननीय नीतीश कुमार, हमारे नेता थे माननीय श्री लालू यादव, हमारे नेता थे राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी । विकास पुरूष, समावेशी विकास, न्याय के साथ विकास का चेहरा, दूसरा चेहरा सामाजिक न्याय के पुरोधा, तीसरा, समरस समाज और साम्प्रदायिक सद्भावना में विश्वास करने वाले सोनिया गांधी और राहुल गांधी । हमलोगों को अपार बहुमत मिला और उस अपार बहुमत के अनुरूप हमने बजट लाने का काम किया है । हमारी सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति तक कुछ करना चाहती है इसलिये हमारा 7 निश्चय है, इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहिये। 2015 के चुनाव में इनसे पूछा जाता था, जनता कहने लगी कि झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पर तेरे मारा गया । काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, याद रखियेगा । मैं कल देख रहा था भाजपा के बड़े नेता, नंद किशोर यादव जी वित्त मंत्री जी से पूछ रहे थे, बता रहे थे पन्ना हमारे पास है, आपने पिछली बार क्या कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 9 वर्षों तक माननीय नीतीश कुमार के संबंध में आपलोगों ने क्या कहा था, आपके सभी नेता क्या कह रहे थे, वह शब्द और वाक्य भूल गये क्या ?

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

हम गौरवान्वित हैं, बिहार के लोग आज गौरवान्वित हैं । हमारा नेता वैसा नेता है जो कल हमारे साथ थे, आज भले ही मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन हमारे नेता के प्रशंसा करते थकते नहीं थे, अघाते नहीं थे और जो लोग हमसे अलग थे, वे लोग आज हमारे साथ हैं, हमारे नेता की प्रशंसा करते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बिहार की आज एक-एक जनता महसूस करती है कि माननीय नीतीश कुमार के शासन में बिहार का समग्र विकास होगा । आपने उन्हें समझाने का कोशिश किया, आपने बतलाया कि नीतीश कुमार से अच्छा व्यक्तित्व और नेतृत्व दूसरा नहीं है । कल आप उनकी प्रशंसा करते थे, आज ये हमारे साथ हैं, ये हमारी प्रशंसा करते हैं । बिहार के लोग गौरवान्वित हैं कि सही मायने में बिहार का विकास करने के लिए अगर कोई एक नेता है, उस

व्यक्ति का नाम है - माननीय नीतीश कुमार । अभी 7 निश्चय पर आना चाहता हूँ, मैं आपको बताऊं.....

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये । एक मिनट में बाकी जो कह रहे हैं, कह डालिये । हमने कहा कि जल्दी से अपनी बात कह डालिये ।

श्री राज किशोर सिंह : महोदय, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वैशाली जनतंत्र की भूमि है, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज सरकार खोले, सरकार उसमें सहयोग करे । इन्हीं बातों के साथ मैं सदन के तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री वित्त विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल और आज यानी 01 मार्च और 02 मार्च, 2016 को 2016-17 का जो प्रस्तुत बजट है या आय-व्ययक है, उसके सामान्य वाद-विवाद पर माननीय सदस्यों ने भाग लिया और कुल 15 माननीय सदस्यों ने पार्टिशिपेट किया इस बहस में । बहस की शुरूआत हमारे 1974 आंदोलन के साथी, नेता विरोधी दल, विधान सभा रहे, मंत्री रहे और उन्होंने खुद कहा कि एक वरीय सदस्य ने बहस की शुरूआत की, मुझे कभी-कभी इन दिनों पर ताज्जुब होता है, नंद किशोर जी आंदोलन के टाईम में बड़ा सौम्य और शालीन व्यक्ति थे मगर आजकल अल्बर्ट पिंटो की तरह उनको गुस्सा क्यों आता है, यह मेरी समझ से बाहर है । मैंने अपेक्षा की थी कि वरीय सदस्य हैं, नेता विरोधी दल रहे हैं और सामान्य वाद-विवाद पर बहुत गम्भीरता से अपनी बातों को रखेंगे ।

महोदय, अपने मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संघीय ढांचा है और यह कहा गया है कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिनका मकसद राज्यहित ही है । हम अपने कार्यक्रम के द्वारा, सरकार के द्वारा कार्यान्वयन कराने की दिशा में काम करते हैं, अनुपालन कराने की कोशिश करते हैं और हमारी जो कमी है, उस कमी को सार्थक ढ़ंग से विपक्ष का दायित्व है कि उसको उजागर करे, सुझाव दे और उसको सरकार गम्भीरता से ले, संशोधित कार्यक्रम या संशोधन अपने कार्यक्रमों में करे । मगर मुझे आश्चर्य हो रहा था, मुझे अपेक्षा थी कि यदि आप वरीय सदस्य हैं, आपने जो सवाल उठाया तो एक संसदीय गम्भीरता का परिचय देना चाहिये और उनको आज यहाँ उपस्थित होना चाहिये था कि उन चीजों को हम सुनें जिन चीजों पर हमने

सवाल उठाया है या सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की है । मगर मुझको लगता है कि आजकल दुखी बहुत हैं । इसकी वजह से गुस्सा उनको बहुत

ज्यादा आता है । उन्होंने क्या-क्या नहीं कहा । (व्यवधान) दुखी का कारण आप तो अच्छा से जानते हैं । जब इधर थे तो ओबामा से नीचे का उदाहरण ही नहीं देते थे । अरे भाई, अब इतनी भी दूरी मत रखिये कि फिर कभी मौका हो साथ मिलने का तो फिर शर्मिंदा होना पड़े, यह अच्छा नहीं लगता है ।

महोदय, उन्होंने जो बातें की, बजट पर कम और राजनीति पर ज्यादा । उन्होंने क्या-क्या कहा । कहा कि आपने अपने बजट भाषण में अपने नेता, गठबंधन और सरकार का जिक्र किया । सरकार की तरफ से यह बजट आता है । यह तो राजनीति का या मंत्रिपरिषद् का क-ख-ग जानने वाला भी व्यक्ति जानता है कि वह सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट है । (व्यवधान)

मुझे अब इस बात की भी खुशी हुई कि मेरी आवाज में भी असर है और उस असर का ही एहसास है ।

श्री नन्द किशोर यादव : असर तो 2011 में भी देखा और आज भी देख रहे हैं । आगे भी देखेंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : एहसास है । असर तो पड़ा कि चलो मेहरबाँ आ गये, थोड़ा-सा लेट ही सही मगर आ गये ।

बजट भाषण में आपने कहा- नेता । अरे भाई, मंत्रिपरिषद् का मुखिया जो होता है वही नेता है । आपको पुरानी बात इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहिये । एन0डी0ए0 सरकार, कहा जाता था - एन0डी0ए0 सरकार । फिर उन्होंने कहा कि इसमें इनका कम है, हमारा ज्यादा है, यह घटक और वह घटक की बात आपने की । मैं उस स्तर पर नहीं जाऊंगा भाई नन्द किशोर जी । ....क्रमशः....

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : (क्रमशः) मगर मैं सिर्फ इशारों-इशारों में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका जो गठबंधन है आज, किससे है ? आपका गठबंधन आदरणीय रामविलास पासवान जी से है.......

श्री नन्दकिशोर यादव : यही बजट में लिखा हुआ है ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : नहीं,नहीं । मैं इन बातों की शुरूआत नहीं करता मगर शुरूआत इस वजह से कर रहा हूँ कि इस सदन का एक वरीय सदस्य ने हमको वहां लाकर खड़ा कर दिया जिससे मुझको उसका पहले जवाब देना मुनासिब लगा । रामविलास पासवान जी, चन्द्रबाबू नायडु जी, स्वर्गीय मुफ्ती सैयद साहेब वगैरह-वगैरह और यहां मांझी जी, कुशवाहा जी वगैरह-वगैरह । आपने सवाल उठाया था सदन में, यह निर्विवाद सत्य है कि यह गठबंधन की सरकार है, हमारे जो कार्यक्रम बनते हैं, वे आपसी राय-मशविरे के तहत बनते हैं और उस कार्यक्रम को सरकार भी अपने कार्यक्रमों में ढ़ालने की कोशिश करती है और सरकार के मार्फत अपने कार्यक्रमों को पेश करती है । यह आम बात है, कोई नई बात नहीं है और कुछ लोगों ने कहा कि 1,44,000 करोड़ कहां से आयेगा, फिर कुछ लोगों ने कहा, आपने ही कहा कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना समाप्त हो गई, बन्द हो गई, फिर लोगों ने कहा कि कहां से आयेगा यह पैसा, इसका जो है इसमें जिक्र नहीं है । फिर कुछ लोगों ने कहा कि कहां से 5 निजी विश्वविद्यालय बना पायेंगे वगैरह-वगैरह । मैं तो इधर के 10 साल के पीरियड को थोड़े देर के लिए छोड़ दे रहा हूँ । जिस राज्य को आप जंगल राज कहा करते थे, उसी जंगल राज में लोकनायक जयप्रकाश विश्वविद्यालय बना और वह किस स्थिति में है, आप जानते हैं । कुँवर सिंह विश्वविद्यालय के बार में आप जानते हैं और बी0एन0मंडल विश्वविद्यालय, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के बारे में आप जानते हैं ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : विश्वविद्यालय नहीं बना था, नामकरण हुआ था ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : बैठ जायं ज्ञानू जी, आप ज्यादा दिन वहां नहीं रहियेगा निश्चिंत रहिए, आपका टौक होता रहता है, मुझे मालूम है । लेकिन आप जहां बैठे हुए हैं, उसको ठीक रखने के लिए कुछ बोलते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है ।

महोदय, अब चूँकि इस वजह से नन्दकिशोर जी, आप सिर्फ बजट पर बोलते हैं, हम बजट पर ही बोलते हैं । मगर आजकल अपना जो है विधायी कार्य कम निभा रहे हैं और आजकल पता नहीं किन कारणों से आप जो है शेरों-शायरी और कविता में ज्यादा मशगूल हो गये हैं ।

श्री नन्दकिशोर यादव : आपसे पुरानी दोस्ती का परिणाम है भैया ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : अच्छा चलिए कम से कम इस बात का तो है । अब जैसे हमारे बारे में यह नहीं, यह नहीं, अब तो यह किसी मकबूल शायर का नहीं है, अपना ही टूटा-फूटा लिखा हुआ है -

मेरा हाथ हाथ, तुम्हारा हाथ कर कमल,
मेरा पैर पैर, आपका पैर पादुका चरण,
मेरा मुँह मुँह, आपका मुँह मुख मंडल ।

श्री नन्दकिशोर यादव : जमा नहीं लेकिन ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : अगर आपके सर से पास कर गया तब हमको अलग से समझाना पड़ेगा ।

श्री नन्दकिशोर यादव : यह तो विजेन्द्र यादव जी के संगत का कमाल है कि पार कर गया ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : महोदय, अब मैं पूर्णरूपेण विषय पर आ जाता हूँ । जैसे 1 लाख 44 हजार करोड़ कहां से आयेगा, कौन योजना है, कैसे इसका कार्यान्वयन होगा, इसका अनुपालन होगा या नहीं होगा, सुशासन के कार्यक्रम थे और ये विकास मिशन के कार्यक्रम कैसे हो गये वगैरह-वगैरह । महोदय, कई माननीय सदस्यों ने मैं उसमें नहीं कहता कि नन्दकिशोर जी भी, उनका हम विपक्ष के नाते आदर करते हैं । जो इनके सार्थक सुझाव हैं, वो मेरे लिए बहुत ही अदब के साथ उसमें जो संशोधन किया जा सकता है कार्यक्रम में और लागू करने में, वह करने की व्यवस्था हम करेंगे । माननीय कई सदस्यों ने अब मैं समय बचाने के लिए सबों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ । महोदय, वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय जैसे आज आय-व्यय पर सरकार का उत्तर हो गया, कल हो सकता है कि थर्ड सप्लीमेंट्री पर भी हो जायेगा । अब उसके बाद मतलब 4 मार्च, 2016 से 28 मार्च, 2016 तक विभिन्न विभागों के द्वारा अपने-अपने डिमांड पेश किये जायेंगे और वह विभाग अपने विभाग का व्यौरा इस सदन पटल पर रखेगा, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और उसपर भी माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा बहस करने का और वो आयेगा । महोदय, प्रत्येक दिन उससे संबंधित प्रभारी उसका जवाब देते ही हैं ।

अब महोदय, वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिसके बारे में जानना चाहता है सदन भी और कुछ लोग भ्रम में हैं, अगर भ्रम निकल गया तो अच्छी बात है और अगर खूँटा गाड़े हुए हैं कि नहीं हम भ्रमित रहेंगे, उसको तो अब्दुलबारी सिद्दिकी क्या, ऊपर के लोग भी आकर के उनका भ्रम नहीं निकाल सकते हैं । वित्तीय वर्ष, अब मैं इसको छोड़

दिया । मैंने इस वजह से भी छोड़ दिया कि यह सारा बजट प्रस्तुत है माननीय आपके नेता सुशील मोदी जी का और इसमें क्या-क्या है, क्या-क्या हुआ है और इसके बारे में नहीं बोलता हूँ, वक्त बचाना चाहता हूँ । मौका मिलेगा, विनियोग पर बोल देंगे, आप घबराईय नहीं । इसपर तो मैं नेता विरोधी दल के हैसियत से सब कुछ बता चुका हूँ और अब उन बातों को छोड़ दीजिए ।

महोदय, वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1,44,696 करोड़ 27 लाख रू0 की राशि का व्यय का बजट प्रस्तावित है । प्रस्तावित है का मतलब कि हम इसमें आगे-पीछे नही जा सकते हैं । बजट तो अनुमानित होता है, अनुमान के आधार पर बनता है, प्रस्तावित है । राशि की उपलब्धतता के संबंध में बजट अनुमान में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से के रूप में 58359 करोड़ 72 लाख रू0, राज्य के अपने करों से 29730 करोड़ 27 लाख रू0, राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व से 2358 करोड़ 11 लाख रू0, केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 34142 करोड़ 14 लाख रू0, मैं आ रहा हूँ उसपर , पूर्व में दिये गये ऋणों के वसूली में 17 करोड़ 38 लाख रू0 और राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण 19299 करोड़ 37 लाख रू0 और केन्द्र सरकार से वाह्य सम्पोषित परियोजनाओं के अन्तर्गत 1955 करोड़ 55 लाख रू0 प्राप्त होना अनुमानित है । अत: व्यय किये जाने वाली राशि का प्रावधान किया गया है । ऐसा नहीं है कि हवा-हवाई है ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने दिनांक 26 फरवरी,2016 को जिस दिन मैंने बजट पेश किया था और अपने वक्तव्य में कहा था कि अगले साल 2016-17 की हमारी राज्य योजना जो कह रहे थे कि सुशासन का कार्यक्रम था, उसको खत्म कर दिया,

...... क्रमश: ....

....क्रमशः...

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : उसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि अगले साल 2016-17 की हमारी राज्य योजना, सुशासन का कार्यक्रम जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चिय सम्मिलित हैं पर फोकस है । मैं आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सात निश्चिय कार्यक्रम अगले पांच वर्षों में पूरे किये जायेंगे न कि 25 वर्षों में और अगले पांच वर्षों में ठीक उसी तरह से पूरे किये जायेंगे, जैसा कि इस सरकार ने पूर्व में अपने आचरण, व्यवहार और अनुपालन कराकर जनता के समक्ष अपनी छवि बनायी है ।

श्री नंद किशोर यादव : यही तो मैंने कहा था वित्त मंत्री जी, मैंने यही आपसे कहा था, आपने जो कहा अभी कि जो आपके सात निश्चिय हैं, वह वैसे ही पूरे किये जायेंगे, जैसे आपकी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में पूरे किये । मैंने इसी का हवाला दिया । आपके सुशासन के कार्यक्रम जो वर्ष 2010-15 के थे, उनका अनुपालन कितना हुआ, क्या आपने उनका आकलन किया क्या ? मैंने उदाहरण दिया आपको, सड़क के बारे में, पानी के बारे में, बिजली के बारे में, ये सारे काम आप नहीं कर पाये पांच साल में तो आपने एक नया तोप छोड़ दिया सात निश्चिय का, उन्हीं बातों को अगले पांच वर्षों में करने का आपने निर्णय लिया, यह तो आप बोल ही नहीं रहे हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : ठीक है, नंद किशोर जी, मैं उसपर आ रहा हूँ । कुछ निश्चिय तो पूरे कर दिये गये । जैसे- महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत् आरक्षण देने से संबंधित था, वह पूरा कर दिया गया है और यह लागू है । हर प्रकार के सरकारी नौकरियों में हर कोटि में जो भी महिला उम्मीदवार होंगे, उनको 35 प्रतिशत् आरक्षण की सुविधा मिल रही है और मिलने जा रही है । महोदय, यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों में वाई:फाई की सुविधा वर्ष 2016-17 में उपलब्ध करा दी जायेगी । राज्य के सभी घरों में बिजली कनेक्सन भी अगले दो वर्षों में उपलब्ध कराने के लिए हमारी वचनबद्धता है और इस दिशा में विपक्ष के नाते नहीं एक आदर्श नागरिक होने के नाते अपने कलेजे पर हाथ रखकर के माननीय सदस्य यह निर्णय ले कि देहातों में बिजली के कार्य हो रहे हैं कि नहीं ?

(व्यवधान)

महोदय, रवीन्द्र जी आपके यहां नहीं हो रहा हे तो करा देंगे । क्यों आप गलत बोल रहे हैं ?

श्री रविन्द्र यादव : पांच-पांच लाख बिजली का बिल आ रहा है, उसपर भी तो आप बोल दीजिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : जहां तक अन्य निश्चियों का सवाल है....

श्री रविन्द्र यादव : बिजली बिल के बारे में बोल दीजिए न ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अभी आप कह रहे थे कि बिजली नहीं लग रहा है और अब आप बिजली बिल पर आ गये । जहां तक अन्य निश्चियों का प्रश्न है, उनपर भी अप्रील,2016 से कार्य आरंभ किये जा रहे हैं और निर्धारित समय के अन्दर उन निश्चियों को पूरा करने की हमारी वचनबद्धता है.....

श्री नंद किशोर यादव : एक बात सिद्दिकी साहेब, आप जानते हैं कि नहीं, आपने सुना होगा पुराना गाना, झूठ बोले कौवा काटे, मेरी चिंता है कि आपको कौवा न काट ले, इसका ध्यान रखियेगा ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : राज्य के सुशासन कार्यक्रम को पूरा करने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता है । हमने अपने राज्य के अपने करों में वृद्धि लाने के लिए कदम उठाये हैं और इसमें हमें अच्छी प्रगति भी प्राप्त हुई है, किन्तु बिहार राज्य को केन्द्र सरकार से जो करों का हिस्सा प्राप्त होता है, उसमें कटौती की जा रही है । यह आपको बुरा लगा था और अब आपने कहा कि साहेब बजट के जरिए केन्द्र सरकार को, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं । हम या आप यहां हैं तो हमारा उद्धेश्य बिहार का हित होना चाहिए । बिहार के हित में ही जब आप यहां थे और सब लोगों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, शायद आपको याद है नंद किशोर जी, अगर याद नहीं है तो हम याद दिला देते हैं । बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जायेगा, सबों ने मिलकर प्रस्ताव पारित किया था । हमारे बिहार के लोगों में और दक्षिण भारत के लोगों में यही फर्क है, वे लड़ते हैं अपनी राजनीति की लड़ाई, मगर राज्य के हित पर नहीं । कावेरी का विवाद हो तो उसमें जो कर्नाटका का स्टेंड हो, चाहे जो भी सरकार आये, वह स्टेंड लेती है । उसी तरह से तमिलनाडू में चाहे जो भी आयें, करूणानिधि जी आयें, चाहे जय ललिता जी आयें, मगर अपने स्टेंड को नहीं छोड़ते हैं । मगर हमारे यहां दुर्भाग्य है कि हम अपनी राजनीति स्वार्थ के लिए बिहार के हित को छोड़कर कई तरह की बात करने लगते हैं ।

श्री नंद किशोर यादव : आपने अभी जो चर्चा किया वित्त मंत्री जी, मैं जरूर चाहूँगा कि जब आपने इस विषय को छेड़ दिया है तो मैं जरूर चाहूंगा आपसे कि रघु राजन कमिटी के रिपोर्ट का क्या हुआ, क्या किया उस कमिटी ने रिपोर्ट, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए

न और जब माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के साथ गलबहियां लगा रहे थे और बड़ी उम्मीद से कमिटी बनाये थे तो कमिटी ने क्या कहा, क्यों नहीं मिला, क्या परिणाम हुआ, इसका भी जिक्र करना चाहिए आपको ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : मैं आपकी पोल खोलने के लिए आज खड़ा हुआ हूँ । आज यू0पी0ए0 सरकार ने बिहार को कितनी राशि दी और एन0डी0ए0 सरकार ने दो साल में बिहार को कितनी राशि दी है, धैर्य से जरा आप सुनेंगे । महोदय, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 14वें वित्त आयोग ने 56हजार300.07 करोड़ रूपये अनुमानित थी । भारत सरकार ने अपने बजट में 56हजार300 की जगह पर 50हजार747.58 करोड़ रूपये का प्रावधान किया । 29 फरवरी, दूबारा लिख लिजिए, हम लिखवा देते हैं, हम आपको भाषण की कौपी दे देंगे । 29 फरवरी,2016 यानी जिस दिन बजट भारत सरकार ने पेश किया है, उस दिन वह और भी घट गया । 29 फरवरी, 2016 को भारत सरकार ने इस प्रावधान को घटाकर 49हजार846.70 करोड़ रूपये कर दिया । अतः वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वित्त आयोग की अनुशंसा से हमें 6453.37 करोड़ रूपये कम उपलब्ध हो रहे हैं ।

श्री नंद किशोर यादव : आप कौन नयी बात बता रहे हैं, नीतीश जी ने तो अपने बजट भाषण में यह बात कह चुके हैं । कोई नया बात कहना हो तो कहें आप ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : हम आ रहे हैं । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 14वें वित्त अयोग ने 64हजार973.82 करोड़ रूपया अनुमानित की है, किन्तु भारत सरकार ने अपने बजट में, यह नीतीश जी नहीं बोले है, जो आप 29 वाला तुलना कर रहे हैं । किन्तु भारत सरकार ने अपने बजट में केवल 55233.71 करोड़ रूपया का ही प्रावधान किया है..........क्रमशः.......

श्री अब्दुल बारी सिद्दकी : क्रमशः......अतः वित्तीय वर्ष-2016-17 में भी हमें 9740.11 करोड़ रूपये कम प्राप्त होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्रीय करों में हमारा हिस्सा जो लोग पूछते हैं कि केन्द्रीय सहायता- वह संवैधानिक व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर है और उस फेडरल स्ट्रक्चर के तहत हमारा हक मिलता है। कोई भीख या मरौव्वत नहीं है, जो बहुत से लोग भ्रम में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनम्रता से अनुरोध करूॅंगा कि केन्द्रीय करों में हमारा हिस्सा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप दिये जाएं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा शेष राशि अधिरोपित की जाती है। नन्दकिशोर जी, आप तो जानते ही होंगे कि जो करों का हिस्सा है उसमें हिस्सेदारी राज्य सरकार को मिलेगा और विभिन्न तरह का जो सेस लगाया जा रहा है उसमें किसी राज्य को कोई हिस्सा मिलता है नहीं। अभी आपने लगाया है डीजल पर, पेट्रोल पर, सी0एन0जी0 पर, चालित गाड़ी पर वगैरह-वगैरह, सर्विस टैक्स पर वगैरह-वगैरह। महोदय, उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा सेस राशि अधिरोपित की जाती है, जो केन्द्र की, राज्य सरकार के केन्द्रीय करों के हिस्से का भाग नहीं बनता। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्र द्वारा अधिरोपित सेस राशि को भी केन्द्रीय करों के राज्य के हिस्से में, भाग में शामिल किया जाय, जिससे राज्य को अतिरिक्त राशि प्राप्त हो सके। अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा सदन में यह कहा गया कि हमारी सरकार- भारत सरकार केन्द्र प्रायोजित प्राप्त योजनाओं में राशि का व्यय नहीं कर पा रही है। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि राशि आपको इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप व्यय ही नहीं कर पाते हैं। उसका आंकड़ा है महोदय, मैं इस संबंध में आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 30934.60 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें तृतीय अनुपूरक की जो राशि विधान मंडल के समक्ष मांगी गयी है वह भी सम्मिलित है। 30934.60 करोड़ रूपये की राशि के विरूद्ध भारत सरकार को फरवरी, 2016 तक 15046.65 यह फरवरी तक का है। यह इतना करोड़ रूपये राशि प्राप्त हुई। मतलब 30934.60 में फरवरी तक मिला 15046 और इसमें खर्च हुआ 12367.24...........

श्री नन्दकिशोर यादव : जरा बताइये न 2012-13 का 2013-14 का उसमें भी आपने नहीं खर्चा किया।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : मैं सुशील मोदी जी की तरह अनुमानित बजट नहीं पेश कर रहा हूॅं कि ये लैप्स कर गया, ये लैप्स कर गया। आप इस मार्च में हमको 15046.65 मिला है। इसको

हमने फरवरी तक 12367.24 खर्चा किया है। बचा हुआ है करीब ढाई या तीन हजार करोड़। वह हर हाल में ये बजट भाषण के खत्म होने के बाद जिन विभागों को राशि दी गयी है, अगर वह समय पर 31 मार्च तक राशि खर्च नहीं करेंगे तो आगे साल से उनके आउटले में कटौती की जायेगी। उनको पैसा कम दिया जायेगा, मगर हम शत प्रतिशत खर्च कराने की कोशिश करेंगे। महोदय, राज्य की वार्षिक योजना में केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इसमें वर्ष 2004-05 तक अभी इसमें महोदय चूंकि बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं और बोलते हैं कि केन्द्र का पैसा है। केन्द्रीय सहायता दी जाती है जिसमें वर्ष 2004-05 तक जो केन्द्रीय सहायता भारत सरकार देती थी उसमें 70 प्रतिशत रिण के रूप में और 30 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में दिया जाता था और निर्धारण गाडगिल फार्मूला के आधार पर निर्धारित किया जाता था। वर्ष 2005-06 से केन्द्रीय सहायता मद में रिण देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी और रिण की उगाही राज्य सरकार द्वारा स्वयं की जाने लगी। वार्षिक योजना 2014-15 में केन्द्र प्रायोजित योजना को राज्य योजना में शामिल कर दिया गया। ऐसी परियोजनाएं जिसमें भारत सरकार सीधे क्रियान्वयन एजेंसी को राशि उपलब्ध कराती थी उसे राज्य के समेकित निधि के माध्यम से व्यय करने के लिए उपलब्ध करा दिया गया। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रांश और राज्यांश दोनों की राशि राज्य योजना से व्यय होने लगी। महोदय, अब इसपर पहले जो राशि मिलती है हमको। पहले गाडगिल फार्मूला था, गाडगिल फार्मूले के तहत राज्य को जो राशि दी जानी थी उसका बेसेज बनाया हुआ था क्राइटेरिया। पहले बना हुआ था आबादी पर 60 अंक, प्रति व्यक्ति आय पर 10, टैक्स इफेक्ट से 10, बिजली एवं सिंचाई से चल रही 10 और विशेष योजना पर 10 यानी इस तरह से 100 प्वाइंट होता था। बाद में इस फार्मूले में सुधार किया गया और प्रति व्यक्ति आय पर 20 प्रतिशत वेटेज दिया जाने लगा। बाद में कई राज्यों ने विरोध किया और कई राज्यों ने कहा कि इसमें सुधार होना चाहिए। तब उस वक्त के जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे प्रणव मुखर्जी। उनकी अध्यक्षता में कमिटी बनी और उसको नाम दिया गया गाडगिल मुखर्जी फार्मूला और गाडगिल मुखर्जी फार्मूला में भी जनसंख्या 60, प्रतिशत व्यक्ति आय 25, वित्तीय प्रबंधन 7.5 और विशेष समस्या 7.5 फिर भी इसी के तहत चूंकि जब बिहार का बंटवारा हो गया, राज्य का पुनर्गठन विधेयक यहां से पास हुआ तो 14वीं वित्त आयोग की सिफारिश के उपरांत केन्द्र सरकार केन्द्रीय विभाज्य पुल से राज्यों को प्राप्त होनेवाले व्यय जो 13वें वित्त आयोग में 32 प्रतिशत थे, उसको बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया। यानी 32 से 42 कर दिया। लोगों को लग रहा है कि 42 कर देने से अब राशि ज्यादा मिलेगी। मोदी सरकार ने काफी इसका प्रचार-प्रसार किया, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने, मगर सच्चाई इससे दिगर है कि खासकर के बिहार जैसे बैकवर्ड राज्यों के लिए। अब इसके तहत

अनुदान हमें जो अन्य मदों में मिलती थी और जो 2000 में इसी विधान सभा का पुनर्गठन विधेयक था, बंटवारा होने के बाद उसके तहत हमें बी0आर0जी0एफ0 का पैसा मिलता था, राष्ट्रीय समविकास योजना में पैसा मिलता था।

टर्न-21/अशोक/02.03.2016

श्री नंद किशोर यादव : आप जो बोल रहे हैं ये सभी आपके बजट भााषण में है, ये सभी बातें आपने कही भी है और आपने लिख कर दिया भी है। आप यह बतायें कि मुख्यमंत्री चापाकल योजना का क्या हुआ ? मुख्यमंत्री नगर विकास योजना का क्या हुआ ? विधायकों के अधिकारों में कटौती का क्या हुआ ? उसकी बात तो कीजिए । आप सिर्फ दुहरा रहे हैं, आपने बजट भाषण में जो लिखकर दिया है वही बात दुबारा कहे जा रहे हैं, यह तो बताइये कि मुख्यमंत्री चापाकल योजना का क्या हुआ ? नगर विकास का क्या हुआ ? विधायकों के अधिकारी की कटौती का क्या हुआ? इसका जवाब दीजिए न!

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : इन बातों का इस रूप में बजट भाषण में उल्लेख नहीं किया गया था । अगर इन बातों का उल्लेख था तब तो कम से कम यह नहीं पूछना चाहिए था कि एक लाख 44 हजार 686 करोड़ कहां से आयेगा ? तब तो यह सवाल नहीं उठाना चाहिए था । महोदय, बी.आर.जी.एफ., जिसमें लगभग 12 हजार करोड़ रूपया बिहार को मिलता था उसका नुकसान हुआ । विपक्ष, अब जैसे गार्डगिल फार्मूला के तहत, उसमें एक माननीय सदस्य थे अभिजित बहुत बड़े मेम्बर थे....

अध्यक्ष : अमृत्य सेन थे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : और ये एकोनॉमिस्ट भी थे और उन्होनें जो जिक्र किया महोदय,, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने सवाल उठाया जरूर कि "About Bihar which gets about 30% of all BRGF grants in part as an obligation under statement of objects and reason for the Bihar Reorganisation Act, 2000 but received a lower devaluation share by our formula then by that of the 13th Finance Commission and also no revnew deficit grant in our award.

तो यह जो फार्मूला बदला तो बिहार ही नहीं, बिहार जैसे अन्य राज्यों को, इसका नुकसान उठाना पड़ा महोदय । अब चूंकि हमने बड़ा धैर्य से सुना था, मगर आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं ? उतावले मत होइये। मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को अपने इस स्टेटमेंट के मार्फत अवगत कराना चाहता हूॅं कि जो लोग ढिंढोरा पीट रहे है कि केन्द्र से बहुत राशि आ रही है, वे किस तरह से बैक डोर से हमारा जो मिलने वाला हक था, उस हक की हकमारी की । अब अगर इसको, अगर इसको आपको लगता है कि हम अपमानित करने के लिए कह रहे हैं-कतइ नहीं । हमारा प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान है, सरकार के प्रति सम्मान है और जो कंस्टीच्यूशन ऑब्लीगेशन है उसका हम आदर करते हैं, मगर हमको अपने बिहार का हक मांगना अगर आप गाली और ये समझते हैं तब तो फिर बिहार की बात करना ही बेकार है ।

महोदय, 2016-17 में प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना में 2-3 तरह से नुकसान हो रहा है- नंद किशोर जी, अब तो आप पावरफुल नेता हैं बी.जे.पी में अब हलांकि अलग बात है हम भी उस वक्त उधर ही थे, मगर हमारा समर्थन था । मगर मैंने पहले कहा था कि नंद किशोर जी पहले बड़ा सौम्य थे, बहुत संस्कारी थे मगर आजकल नंद किशोर जी पर गुस्सा क्यों हावी हो गया ? उस वक्त भी आपने कहा था अरे चार महीना में आपलोग जाने वाले हैं, बोले थे न ! उस दिन भी गुस्से में थे । लोकतंत्र में ईर्षा, द्वेष, घृणा को कभी भी जनता बर्दाश्त नहीं करती है ।

श्री नंद किशोर यादव : ये जो आप बोलते हैं अपने पर लागू भी तो करें, अपने सरकार को कहिये लागू करे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : क्या चीज को लागू करने के लिए कह रहे हैं ?

श्री नंद किशोर यादव : आप जो बोल रहे हैं अपने सरकार को समझाइये कि वे इसको लागू भी करें न ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: सरकार हम नहीं है क्या ? सरकार हम नहीं है क्या ? आप दस साल रहे मंत्रिपरिषद् में, ज्वायंट रिसपौसब्लिटी है मंत्रिपरिषद् के माननीय सदस्यों का ।

श्री नंद किशोर यादव : आपकी बात को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: स्वीकार करे या नही करे, नहीं कर रहे हैं क्या ? (व्यवधान) आप स्वीकार कर लिये न !

महोदय, जो शंयरिंग पैटर्न बदला भारत सरकार के द्वारा उससे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों का नुकसान हुआ- यह सच्चाई है । महोदय, वित्तरीय वर्ष 2016-17 में मतलब उदाहरणस्वरूप प्रधानमंत्री ग्राम्य.....

श्री नंद किशोर यादव : आप यह भी बतला देते कि यह जो शंयरिंग पैटर्न बदला, उसमें भारत सरकार कहां है ? शेयरिंग पैटर्न जो बदला, देश का जो राजस्व है, इसका जो हिस्सा बंटता है- यह कौन तय करता है ? यह फाईनेन्स कमीशन तय करता है या नहीं करता है ? राज्यों से बात करके करता है कि नहीं करता है । आपने अपनी बात कही थी कि नहीं कही थी ? आपके राज्य के आबादी के हिसाब से लाभ मिला कि नहीं मिला ? यह जो तय करता है आयोग तो मुझे क्यों गाली देते हो ? आप मुझे क्यो दोषारोपित करते हो ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: नंद किशोर जी यह समझाईयेगा उसको जो बेचारे नासमझ हैं । फाइनेन्स कमीशन, फाइनेन्स कमीशन भारत सरकार से बाहर है क्या ? फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट मानना या न मानना- क्या हमारे लिये यह ताबीज है क्या ? आप पूछे थे क्या कि आप योजना आयोग क्यों भंग कर रहे हैं और नीति आयोग क्यों बना रहे हैं और नीति आयोग बना दिया तो नीति आयोग दो साल में क्या किया ?

श्री नंद किशोर यादव :बात बदलिये नहीं । जो सवाल खड़ा कीजिए तो उसका जवाब दीजिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: फाइनेन्स कमीशन का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर राज्यों को विशेष राज्य की सुविधा मिलती तब तो क्राईटेरिया के हिसाब से चलता, फाइनेन्स कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, उसकी समीक्षा सरकार करती है और फाइनेन्स कमीशन जो एक संवैधानिक एक तरह से मिला हुआ है पावर, उस पर तरमीम कराने का या उसको संशांधित करने का ऐक्ट बनाने का, विशेष सुविधा देने का केन्द्र सरकार को और राज्य सरकार से जो संबंधित मामला है, पूरा अधिकार है इसलिए भर्माइये मत । महोदय, अब चूकि पहले मिलता था प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना, पहले केन्द्र सरकार से शत-प्रतिशत....

श्री नंद किशोर यादव : मुख्यमंत्री ग्राम्य सम्पर्क सड़क योजना का हाल तो बतलाइये न ! आप कहां चले जा रहे हैं? भारत सरकार के बजट पर भाषण हो रहा आपका क्या ? महोदय राज्य के बजट पर भाषण हो रहा है, मुख्यमंत्री ग्राम्य सम्पर्क सड़क योजना का क्या हुआ यह बताइये । चापाकल का क्या हुआ यह न बताइये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: आ रहे हैं, आ रहे है । आप अभी जाइयेगा नहीं न ! अभी बैठिये न, कहां जाइयंगा ?

अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय नंद किशोर जी जब बोलते हैं तो ये भी महोदय कर के बोलते हैं और आप भी बोलते हैं तो अध्यक्ष महोदय कह कर बोलते हैं लेकिन जब हम आपकी तरफ देखते हैं तब आप उनको देखते हैं, जब हम इनको देखते हैं तो ये आपको देखते हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: हमारा घ्यान ठीक ही आकृष्ट किया महोदय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : इनकी तरफ देखते हैं तो प्रेम बाबू ऊपर देखते हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना में शत-प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार मुहैया कराती थी अब जो नया शेयरिंग का जो बदला है तरीका इसमें 60: 40 हो गया, 40 प्रतिशत राज्य सरकार को अपने आन्तरिक श्रोत से इकाट्ठा करके लगाना होगा । महोदय, इसी प्रकार से इन्दिरा आवास योजना में शेयरिंग पैटर्न 75:25 से घटाकर 60:40 किया गया । केन्द्र सरकार ने ज्यादातर शेयरिंग पैटर्न योजनाओं में 60:40 कर दिया है, इससे वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार को लगभग 4508.63 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ा । क्रमशः

टर्न-22/02-03-2016/ज्योति

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : इससे वित्तीय वर्ष 15-16 में राज्य सरकार को लगभग 4 हजार 508. 63 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा और आग ेभी भार वहन करना पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से किसी राजनीति के तहत नहीं मगर चूंकि उस एकरारनामें परे आपका भी सिग्नेचर है और हम दोनों की मंशा बिहार की तरक्की और बिहार का हित हा इसकी है` इसलिए मैं पुनः बिहार जैसे पिछड़े राज्य जिसके बारे में लोग कहते हैं बिहार पिछड़ गया , गुजरात कहॉ चला गया, तमिलनाडु कहॉ चला गया वगैरह वगैरह तो मैं मांग करता हूॅं कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाय और मुझको लगता है एकरारनामा तो किये हुए हैं अब तो मुकर नहीं सकते हैं । इसपर तो आपको

आपत्ति नहीं है - कि है ? नहीं बोल दीजिये मैं बैठ जाता हूँ । आपको अगर आपत्ति है तो बोल दीजिये , हम दो मिनट बैठ सकते हैं आप बोल दीजिये ं।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, ये चाहते हैं अब नहीं बोलना इसलिए अपना टाईम अपने किल कर रहे हैं । मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ आपको जो कहना हो कहिये । लेकिन राज्य के बजट के बारे में कहिये । आप 7 निश्चयों को पूरा करने के लिए बजट में पैसा कहाँ से लायेंगे इसके बारे में कहिये । आपने चापाकल योजना क्यों बंद कर दी , नगर विकास योजना क्यों बंद कर दी और मैंने सवाल खड़ा किया था 7 निश्चयों के बारे में जिन विभागों द्वारा लागू किया जाने वाला है उसमें से अधिकांश विभंागों पर आपने अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं रखा है इन सब बातों के बारे में बोलिए न आप । जो बिहार से जुड़े हुए सवाल है जो मैंने खड़े किए हैं उन सब पर नहीं बोल रहे हैं , समय अपना बर्बाद कर रहे हैं , आप बोलना नहीं चाहते हैं , आप बोल नहीं सकते हैं इसलिए अपना समय अपने बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : आपके कहने पर बॉय काट आजकल नहीं हो रहा है , नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार जी हैं समझे कि नहीं । बात असल है कि जो चीज बिहार की जनता जानना चाहती है जिस एकरारनामे पर आपने दस्तखत किया है उसपर आप अडिग हैं कि नहीं इतना बोल दीजिये ।

श्री नन्द किशोर यादव : पहले जो सवाल खड़ा किया है उसका जवाब दे दीजिये । भागिये नहीं आप । आपके भागने से काम नहीं चलेगा । आपको बोलना पड़ेगा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : ऊपर में पत्रकार लोग बैठे हुए हैं कह रहे हैं नहीं, नंदकिशोर जी अडिग है , कायम हैं , ठीक है ं ? महोदय, जैसे विशेष राज्य का दर्जा दीजिये जिससे इन योजनाओं में हमें 90-10 का रेशियो मिले और राज्य के विकास के काम करने में हमें सहूलियत हो सके ।

श्री प्रेम कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ओर जहाँ प्रधानमंत्री जी और केन्द्रीय वित्त मंत्री जी चाहते हैं कि देश में महंगाई कम रहे वहीं राज्य सरकार ने पहली बार बिहार पहला राज्य है यहाँ कपड़ा पर , साड़ी पर , खाने की वस्तुओं पर , डीजल -पेट्रोल पर , वैट बढ़ा के महंगाई को जो थोपने का काम कर रहे हैं हम चाहेंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी से कि आपने लगभग 650. वस्तुओं पर रोटी , कपड़ा , मकान जो हर व्यक्ति के लिए जरुरी है टैक्स लाद कर आम जनता पर टैक्स लादने का जो काम किया है इसके बारे में महोदय, हम जानना चाहेंगें आपके माध्यम से कि सरकार एलान करे कि देश के किसी राज्य में कपड़ा पर टैक्स नहीं है लेकिन पहली बार

बिहार में जजिया टैक्स लगाने का काम सरकार कर रही है जिसका हम लोग विरोध करते हैं इसलिए हमलोग बॉयकाट कर रहे हैं ।

(इस अवसर पर भजपा के माननीय सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया)

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : चले गए प्रेम जी । महोदय, भारत सरकार के प्रस्तुत बजट में –यह महोदय, भारत सरकार का बजट जो 29 तारीख को पेश किया गया है उसकी यह कॉपी है और मुझको लगता है कि यह 72 या 75 पेज हैं का है अब अगर माननीय सदस्य लोग यहाँ बैठते अगर नहीं भी बैठे तो उनको अगर केन्द्रीय बजट की कॉपी नहीं मिली है तो उनको भेजवा दूँगा । इस बजट में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री ने बिहार में आकर लाखों बिहारियों के समक्ष जो यह वादा किया था कि 1 लाख 25 हजार करोड़ का विशेष पैकेज दिया जायेगा वह पैकेज की बात नहीं है और कहते हैं कि साहब एक माननीय नेता हैं पूर्व उपमुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि नहीं इस बजट में उन चीजों का उल्लेख है । मैं कहता हूँ कि इन चीजों की समीक्षा करके वे प्रेस कौन्फ्रेंस करके बतला दें कि 1 लाख 25 हजार करोड़ का कहाँ जिक्र है । महोदय, मैं अब चूँकि ये हैं नहीं महोदय, बिहार राज्य को प्रत्येक स्कीम में कितनी राशि प्राप्त होगी । राशि की स्पष्टता संबंधित मंत्रालय द्वारा राज्य वार , स्कीम वार , उद्व्यय निर्धारण के पश्चात ही स्पष्ट हो सकता है । वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय सहायता की परियोजनाओं के लिए विभाग के सूचनाओं के आधार पर प्राप्ति दिखलायी गयी है । भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों नीति आयोग से स्कीम वार बिहार राज्य को कितनी राशि प्राप्त होगी इसकी सूचना अबतक मिली नहीं है । मिलने पर केन्द्रीय सहायता मद में विभिन्न परियोजनाओं में मद वार राशि के प्रावधान में संशोधन होगा और जिससे वार्षिक योजना के आकार में महोदय, कमी या वृद्धि हो सकती है । महोदय, 2016-17 में योजना और गैर योजना - चले गए कि कहाँ से आयेगा मैं 1 लाख। 44 हजार करोड़ तो महोदय, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको ले कर देता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(परिशिष्ट -1 पर द्रष्टव्य है)

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : अंत में महोदय, यह जो बजट है यह बहुत सोच समझकर, मेहनत करके और मैंने अपनी पीठ कतई थपथपाई नहीं है, मैंने पहले ही कहा है कि गठबंधन सरकार बनने के बाद यह गठबंध।न सरकार का पहला बजट है इसलिए समय की कमी रही , मगर कमी के बावजूद हमने जो फोकस किया है जिन क्षेत्रों

को उन क्षेत्रों को अमलीजामा पहनाने का दायित्व इस सरकार का है , सरकार की वचनबद्धता है कि गली , नाला, रोड ,पुल ,पुलिया जितने भी शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं उसमें अगर हमारी तरफ से त्रुटि होगी माननीय सदस्य को हक है हमारा ध्यान आकृष्ट करने का और अगर हम पॉच साल तक अपने वादाखिलाफी करते रहे तो पॉच साल के बाद फिर चुनाव आयेगा । हम जानते हैं कि पॉच साल हम इतना काम करेंगे कि इनकी जितनी तादाद अभी है यहॉ भी और वहॉ भी कम होने वाली है । ये जाने वाले हैं । महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करने के पूर्व अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों ने बहुत ही धैर्य से ,एकाग्रता से मेरी बातों को अनुश्रवण किया इस वजह से हमारी भी यह जिम्मेदारी है , दायित्व है कि 2016-17 में राज्य सरकार अपनी वित्तीय प्रबंधन को और सुदृढ़ करेगी और समावेशी स्थायी विकास के साथ उच्च वृद्धि दर को हासिल करेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सदन के माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ । धन्यवाद !

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण , सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श समाप्त हुआ।

आज दिनॉक 2 मार्च 2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 18 है अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें सबंधित विभागों को भेज दिया जाये।

(सदन की सहमति हुई)

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार दिनॉक 3 मार्च 2016 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट–1

Amount Received From GOI As a Grants							
							Rs in Crore
Year	Non Plan (01)	Sate Plan (02)	CSS (04)	CPS (03)	**Total**	Direct Agency Transfer	**Grand Total**
UPA Preiod							
2004-05	683.99	1642.90	494.61	10.32	2831.82		**2831.82**
2005-06	1205.28	1551.46	485.98	89.99	3332.71		**3332.71**
2006-07	1683.41	2445.24	974.16	144.29	5247.10		**5247.10**
2007-08	1505.07	2913.83	1359.50	53.25	5831.65		**5831.65**
2008-09	2550.44	3600.09	1676.65	134.94	7962.12	2925.27	**10887.39**
2009-10	2256.2	3720.97	1449.28	137.71	7564.16	3414.75	**10978.91**
2010-11	1924.78	5456.95	2141.13	175.70	9698.56	10309.09	**20007.65**
2011-12	2562.62	5065.39	2159.19	95.78	9882.98	8957.91	**18840.89**
2012-13	2412.58	5051.97	2777.68	35.69	10277.92	8314.38	**18592.30**
2013-14	3288.14	6238.39	2920.85	136.65	12584.03	9464.50	**22048.53**
NDA Preiod							
2014-15	3271.22	14935.68	821.88	117.48	19146.26	651.74	**19798.00**
2015-16 (Up to Feb 2016)	2275.86	15046.65	0.00	154.64	17477.15		**17477.15**
2016-17 (B.E)	4516.22	28777.82	0.00	848.10	34142.14		**34142.14**